अध्याय

05

मध्यम अवधि का परिदृश्य: गैर-विनियमन से विकास को बढ़ावा

क्या हम रोचक समय में जी सकते हैं![1] यह चीनी कहावत, जिसे अक्सर संभावित अशांति के संकेत के रूप में समझा जाता है, प्रासंगिक है। विश्व भर में, हम आर्थिक एकीकरण को पिछड़ते हुए देख रहे हैं जहां भू-आर्थिक विखंडन वैश्वीकरण का स्थान ले रहा है। आर्थिक पुनर्संरेखण और पुन: समायोजन अवश्यसंभावी हैं। विनिर्माण महाशक्ति के रूप में चीन का उदय और अन्य देशों की विनिर्माण आकांक्षाओं पर इसके प्रभाव के साथ-साथ ऊर्जा संचरण के लिए आवश्यक खनिजों, सामग्रियों, मशीनरी और उपकरणों की आपूर्ति चुनौतियां पेश करती है।

इन सबके बीच, भारत ऐसे बदलाव के मध्य है जो किसी अभूतपूर्व आर्थिक चुनौती और अवसर का द्योतक है। यह अध्याय भारत की कहानी की विवेचना करता है। इसमें विकास के घरेलू नियंत्रकों और विनियामक अनुपालन बोझ को कम करने के महत्व पर जोर देने के साथ-साथ नितिगत उपायों को सुझाया गया है।

भारत का मध्यावधिक दृष्टिकोण

5.1 भारत को स्वतंत्रता की शताब्दी तक विकसित भारत की अपनी आर्थिक आकांक्षाओं को साकार करने के लिए लगभग एक या दो दशक तक स्थिर मूल्यों पर औसतन 8% की वृद्धि दर प्राप्त करने की आवश्यकता है। हालांकि इस विकास दर की वांछनीयता निर्विवाद है, फिर भी यह स्वीकार करना महत्वपूर्ण है कि वैश्विक वातावरण-राजनीतिक और आर्थिक-भारत के विकास परिणामों को प्रभावित करेगा।

5.2 वित्त वर्ष 2025 के अक्टूबर में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (इस अध्याय के बाकी भागों में आईएमएफ या कोष के रूप में संदर्भित) के विश्व आर्थिक परिदृश्य (डब्ल्यूईओ) की नजर से भारत के लिए अनुमान को देखते हुए ऐसा स्थान आशावादी है। आईएमएफ डब्ल्यूईओ का अनुमान है कि भारत वित्त वर्ष 2028 तक 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बन जाएगा और वित्त वर्ष 2030[2] तक 6.307 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था हो जाएगा। (चार्ट V.1) यह वित्त वर्ष 2025 से वित्त वर्ष 2030 की अवधि के लिए अमेरिकी डॉलर के संदर्भ में 10.2% प्रतिशत वार्षिक नामिक विकास दर में परिवर्तन को दर्शाता है। इसे संदर्भ में रखने के लिए, वित्त वर्ष 1994 और वित्त वर्ष 2024 के बीच के तीस वर्षों में,

1 इस उद्धरण को प्राचीन चीनी अभिशाप की अपोक्रिफल अंग्रेजी व्याख्या के रूप में समझा जाता है और इसे कई व्यक्तियों के लिए गलत तरीके से जिम्मेदार ठहराया गया है। वैन नॉर्डन, ब्रायन विलियम (2011)। "II- क्रिटिसिज्म्स एंड कंफ्यूसिनियनिज्म" इंट्रोडक्शन टू क्लासिकल चाईनीज फिलॉस्फी [पी. 257]

2 अय्यर, एस, जे चेन, सी एबेके, आर गार्सिया-साल्टोस, टी गुडमंडसन, ए इलिना, ए कंगूर, एस रोड्रिग्ज, एम रूटा, टी शुल्ज, जे ट्रेविनो, टी कुनारत्कुल और जी सोडरबर्ग (2023), षजियोइकोनॉमिक फ्रैग्मेंटेशन एंड द फ्यूचर ऑफ मल्टीलैटरलिज्मष, आईएमएफ स्टाफ डिस्कशन नोट एसडीएन/2023/01।

भारतीय डॉलर जीडीपी 8.9% की वार्षिक चक्रवृद्धि दर से बढ़ी। अतः आइएमएफ यह आशा करता है कि आगामी पाँच वर्षों में भारत डालर के संदर्भ में 10.2% की महत्वपूर्ण उच्च दर से वृद्धि करेगा।

चार्ट V.1: वित्त वर्ष 2025 से वित्त वर्ष 2030 तक आईएमएफ डब्ल्यूईओ का भारत के लिए अनुमान

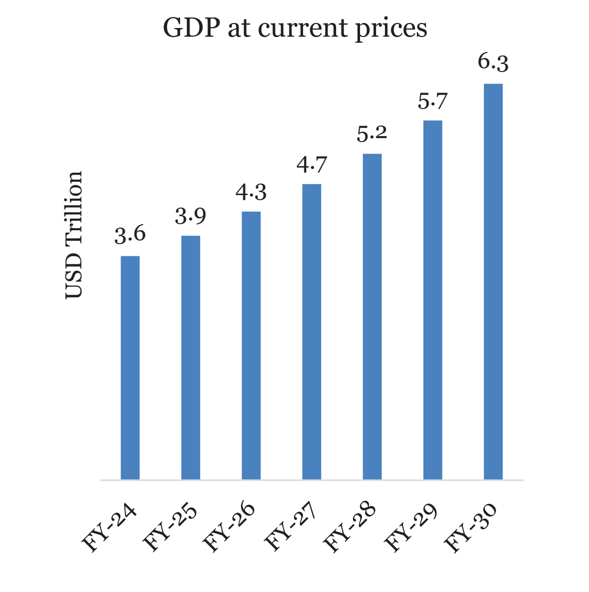

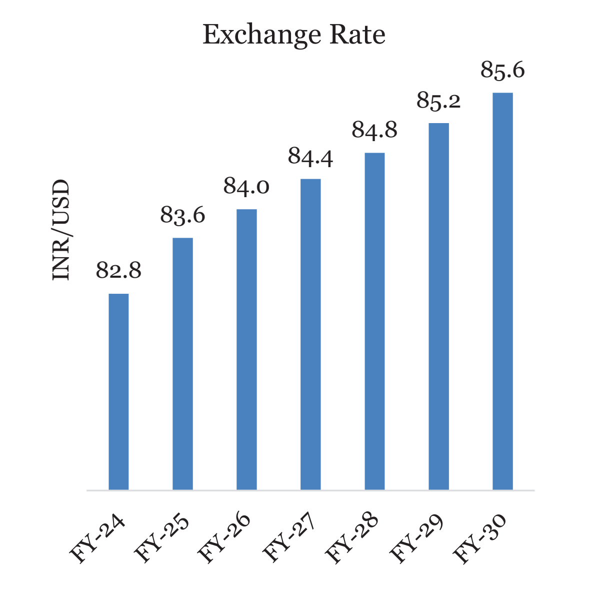

स्रोत: डब्ल्यूईओ, अक्टूबर, 2024

5.3 रुपये के संदर्भ में, भारत का नामिक जीडीपी वित्त वर्ष 2024 को समाप्त होने वाले तीन दशकों में 12.4% की वार्षिक चक्रवृद्धि दर से बढ़ा है। अगले पांच वर्षों में, आईएमएफ का अनुमान है कि भारत का नामिक जीडीपी प्रतिवर्ष लगभग 10.7% बढ़ेगा। इसलिए, वास्तव में, डॉलर के संदर्भ में केवल 10.2% की अनुमानित वृद्धि दर को देखते हुए, कोष को उम्मीद है कि अगले पांच वर्षों में रुपया औसतन प्रति वर्ष केवल 0.5% तक कमजोर होगा, जबकि वित्त वर्ष 2024 तक के तीन दशकों में 3.3% वार्षिक मूल्यह्रास देखा गया। रुपये में मामूली गिरावट भारत की विकास क्षमता, निवेश गंतव्य के रूप में इसका आकर्षण और भारत की मुद्रास्फीति दर के संयुक्त राज्य अमेरिका के समतुल्य होने की आशा की मान्यता है। इस कोष का यह भी अनुमान है कि भारत का चालू खाता घाटा वित्त वर्ष 2030 तक धीरे-धीरे और क्रमिक रूप से बढ़कर जीडीपी का 2.2% हो जाएगा। इस बात की पुनरावृत्ति की जाती है कि, विश्व की वर्तमान स्थिति और इसके संभावित विकास को देखते हुए, इन अनुमानों को साकार करना भारत के लिए बहुत अच्छी बात होगी।

5.4 वित्त वर्ष 2025 के लिए आर्थिक विकास का पहला अग्रिम अनुमान जारी कर दिया गया है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय का मानना है कि अर्थव्यवस्था स्थिर कीमतों पर 6.4 प्रतिशत की दर से बढ़ेगी। वित्त वर्ष 2026 के लिए, हमने इस सर्वेक्षण के पहले अध्याय में 6.3 प्रतिशत से 6.8 प्रतिशत के बीच की वृद्धि दर का अनुमान लगाया है। यह वित्त वर्ष 2026 और वित्त वर्ष 2030 के बीच लगभग 6.5% पर स्थिर कीमतों पर भारत के जीडीपी की विकास दर के संबंध में अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष के अनुमान के अनुरूप है। इस अध्याय में इन विकास दरों को प्राप्त करने या उससे आगे बढ़ने में हमारी

मदद करने के लिए नीतिगत कार्रवाई एजेंडा की विवेचना की गई है।

5.5 इसकी शुरूआत वैश्विक आर्थिक और राजनीतिक वातावरण को रेखांकित करके होती है। खंड I भू-आर्थिक विखंडन की वास्तविकता का अन्वेषण करता है और वैश्विक विकास के लिए इसके निहितार्थों की जांच करता है। खंड II एक स्पष्ट अंतर्निहित समस्या (और चीन) को स्वीकार करने के मामले को रेखांकित करता है जिसका विकास अनुमानों – चीन के विनिर्माण कौशल और रणनीतिक प्रभुत्व के साथ वैश्विक आर्थिक व्यवस्था में मौलिक बदलाव पर असर पड़ेगा। अगला खंड (III) चीन के प्रभुत्व के थोड़े कम स्वीकृत किन्तु महत्वपूर्ण पहलू से संबंधित प्रमुख साधन अर्थात् ऊर्जा संचरण प्रयासों के लिए वैश्विक अर्थव्यवस्था पर उसकी निर्भरता की जांच करता है। ग्रीनहाउस गैसों के सबसे कम प्रति व्यक्ति उत्सर्जकों में से एक होने के बावजूद भारत में ऊर्जा संचरण के लिए महत्वाकांक्षी लक्ष्य हैं। उस ऊर्जा संचरण को हासिल करने के लिए चीनी-निर्मित वस्तुओं पर निर्भरता से भारत के लिए चुनौती और भी जटिल हो जाती है। अगला खंड (IV) वैश्विक संदर्भ और उल्लिखित चुनौतियों के मद्देनजर भारत के लिए घरेलू विकास के नियंत्रकों पर बल देने की आवश्यकता पर ध्यान केंद्रित करता है। यह लोगों और संगठनों की सरलता पर भरोसा करने और उनकी आर्थिक स्वतंत्रता को बढ़ाने के लिए नीति का उपयोग करने का मुद्दा बनाता है जो डब्ल्यूईओ के अनुमानों के अनुरूप विकास को गति देगा। अंतिम खंड (V) व्यवस्थित गैर-विनियमन के विशिष्ट पहलुओं पर गहराई से चर्चा करता है, जिनपर व्यक्तियों और व्यवसायों के लिए आर्थिक स्वतंत्रता को सुविधाजनक बनाने हेतु ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है ताकि भारत की मध्यावधिक विकास संभावनाएं सुदृढ़ कायम रह सकें।

भू-आर्थिक विखंडन- इस बार स्थिति अलग हो सकती है

5.6 अपने महत्वपूर्ण लेख '*द इकॉनोमिक कॉन्सिक्वेन्सेस ऑफ पीस*' में जॉन मेनार्ड कीन्स ने बीसवीं सदी के आरंभिक लंदन के बारे में लिखा है कि '*लंदन का निवासी सुबह की चाय बिस्तर पर पीते हुए टेलीफोन पर पूरी दुनिया की विभिन्न उत्पादनों को, अपनी इच्छानुसार मात्रा में, मंगवा सकता था और उम्मीद कर सकता था कि वे उसके घर तक जल्दी ही पहुंच जाएंगी; वह उसी समय और उसी साधन से विश्व के किसी भी कोने के प्राकृतिक संसाधनों और नए उद्यमों में अपनी आस्ति लगा सकता था और बिना किसी परिश्रम या परेशानी के उनके संभावित प्राप्तियों और लाभों में हिस्सा प्राप्त कर सकता था*'।

5.7 कीन्स ऐसी स्थिति का वर्णन कर रहे थे जिसमें वैश्वीकरण के पिछले कुछ दशकों में हमारे लिए एक अलग स्थिति बन गई है, जिसमें पूंजी, माल, सेवाओं और लोगों के प्रवाह ने हमारी विश्व को बदल दिया है, जिसमें नई प्रौद्योगिकियों और विचारों के प्रसार ने सहायता की है। एकीकरण की इन शक्तियों ने उत्पादन और जीवन स्तर का संवर्धन किया है, वैश्विक अर्थव्यवस्था के आकार को तीन गुना बढ़ा दिया है और 1.3 बिलियन लोगों को अत्यधिक गरीबी से बाहर निकाला है।

5.8 तथापि, कीन्स के वर्णन की ही भांति कि कैसे लंदनवासियों की समृद्धि '*सैन्यवाद और साम्राज्यवाद की योजनाओं और राजनीति, नस्लीय और सांस्कृतिक प्रतिस्पर्धाओं, एकाधिकार, प्रतिबंध और बहिष्कार*' के कारण नष्ट हो गई, हम वर्तमान युग के साथ असहज समानताएं संरेखित कर सकते हैं, जिसमें वैश्विक अर्थव्यवस्था एक बार फिर भू-आर्थिक विखंडन (जीईएफ) की चुनौती का सामना कर रही है। इस बार,

इसका पैमाना, दायरा और जटिलता इतनी अधिक है कि इसका प्रभाव संभवतः 20वीं सदी के आरंभ में विश्व ने जो देखा था, उससे भी अधिक गंभीर है।

5.9 1980 के दशक के बाद के दशकों में महत्वपूर्ण वैश्वीकरण देखा गया है, जिसमें वैश्विक व्यापार, निवेश और आर्थिक गतिविधि में उल्लेखनीय बदलाव हुए हैं। यहाँ कुछ प्रमुख आँकड़े दिए गए हैं:

वैश्विक व्यापार वृद्धि: वर्ष 1980 में, वैश्विक व्यापार का विश्व सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 39 प्रतिशत का योगदान था। वर्ष 2012 तक, यह हिस्सेदारी बढ़कर 60 प्रतिशत हो गयी थी, जो वैश्विक बाजारों के मजबूत एकीकरण को दर्शाता है।

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई): वैश्विक एफडीआई अंतर्वाह 1980 में 54 बिलियन डॉलर से बढ़कर 2019 में 1.5 ट्रिलियन डॉलर से अधिक हो गया, जो सीमा-पार निवेश में बहुराष्ट्रीय निगमों की बढ़ती भूमिका को दर्शाता है।

आर्थिक विकास और गरीबी में कमी: वैश्विक अर्थव्यवस्था 1980 में 11 ट्रिलियन डॉलर से बढ़कर 2022 में 100 ट्रिलियन डॉलर (सांकेतिक रूप से) से अधिक हो गई।

वैश्विक जनसंख्या और शहरीकरण:

वैश्विक जनसंख्या 1980 में 4.4 बिलियन से बढ़कर 2022 में 8 बिलियन हो गई, शहरीकरण दर 1980 में 39% से बढ़कर 2022 में 57% हो गई, जिससे आर्थिक गतिविधियों और कनेक्टिविटी को बढ़ावा मिला।

इंटरनेट का प्रसार: 1980 में इंटरनेट कनेक्टिविटी लगभग न के बराबर थी। 2022 तक, 5.3 बिलियन से ज्यादा लोगों या वैश्विक आबादी के 66% लोगों के पास इंटरनेट की पहुँच थी, जिससे संचार, व्यापार और नवाचार में क्रांति गई।

ये आंकड़े दर्शाते हैं कि वैश्वीकरण ने आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा दिया है और वैश्विक आर्थिक परिदृश्य को बदला है। लेकिन, अगले दो दशकों में आर्थिक विखंडन की संभावना अधिक है।

5.10 अय्यर और अन्य (2023)[3] 'भू-आर्थिक विखंडन' को वैश्विक आर्थिक एकीकरण के नीति-प्रेरित परिवर्तन के रूप में परिभाषित करते हैं, जो अक्सर रणनीतिक विचारों द्वारा निर्देशित होता है। यह प्रक्रिया व्यापार, पूंजी और प्रवास प्रवाहों सहित विभिन्न चौनलों को शामिल करती है[4]। एकीकरण के लाभों के बावजूद, वैश्वीकरण संबंधित आत्मसंतुष्टि भी लाई है। वैश्विक प्रतिस्पर्धा के बीच उद्योगों में बदलाव के कारण लोग पीछे छूट गए हैं। बढ़ते भू-राजनीतिक तनावों और युद्ध के छिड़ने से वैश्विक अर्थव्यवस्था में ये अंतर्निहित दरारें और भी गहरी हो गई हैं।

5.11 शीत युद्ध के दौर की पुनरावृत्ति में, देश एक बार फिर दो गुटों में बंट रहे हैं और फ्रेंडशोरिंग

3 Aiyar, S, J Chen, C Ebeke, R Garcia-Saltos, T Gudmundsson, A Ilyina, A Kangur, S Rodriguez, M Ruta, T Schulze, J Trevino, T Kunaratskul and G Soderberg (2023), "Geoeconomic Fragmentation and the Future of Multilateralism", IMF Staff Discussion Note SDN/2023/01.

4 https://cepr.org/voxeu/columns/geo-economic-fragmentation-and-world-economy

जैसे वाक्यांश वैश्विक नीति निर्माण में केंद्रीय भूमिका निभाने लगे हैं। व्यापार, प्रौद्योगिकी मानकों और सुरक्षा को लेकर तनाव कई वर्षों से बढ़ रहे हैं, जिससे मौजूदा वैश्विक आर्थिक प्रणाली में विकास और भरोसा भी कम हो रहा है। इसलिए, विखंडन-आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक-पश्चिमी देशों द्वारा 'वन-साइज-फिट्स ऑल' उत्सर्जन तथा सामाजिक और श्रम मानकों को लागू करने का प्रत्यक्ष परिणाम है। इन घटनाक्रमों का विकास पर प्रभाव पड़ता है।

भू-आर्थिक विखंडन के विकास संबंधी निहितार्थ

5.12 जीईएफ के परिणाम और लागत उन सभी माध्यमों के जरिए प्रचारित किए जाते हैं जिनके माध्यम से देश एक-दूसरे के साथ आर्थिक रूप से जुड़ते हैं। व्यापार वह मुख्य चौनल है जिसके माध्यम से विखंडन वैश्विक अर्थव्यवस्था को नया आकार दे रहा है। उद्योग के भीतर पुनर्वितरण को प्रोत्साहित करने और उत्पादकता लाभ उत्पन्न करने के लिए व्यापार की क्षमता तेजी से कम होती जा रही है। यह देशों द्वारा आरोपित व्यापार-प्रतिबंधात्मक उपायों में वृद्धि में सबसे अधिक स्पष्ट है। विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) द्वारा डब्ल्यूटीओ महानिदेशक के वैश्विक व्यापार विकास के वार्षिक अवलोकन के हिस्से के रूप में जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार, नवंबर 2023 में अंतिम व्यापार निगरानी रिपोर्ट की तुलना में अक्टूबर 2023 के मध्य और अक्टूबर 2024 के मध्य डब्ल्यूटीओ सदस्यों द्वारा व्यापार-प्रतिबंधात्मक उपायों के कवरेज में तीव्र वृद्धि हुई है [चार्ट V.2]।

5.13 अनुमानों के अनुसार, अक्टूबर 2023 और अक्टूबर 2024 के बीच शुरू किए गए 169 नए व्यापार-प्रतिबंधात्मक उपायों में कवर किए गए व्यापार का मूल्य 887.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर है, जो कि पिछले वर्ष शुरू किए गए प्रतिबंधों के तहत कवर किए गए व्यापार के मूल्य जो कि 337.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर[5] था से आधा ट्रिलियन डॉलर अधिक है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष[6] ने पाया कि शीत युद्ध की शुरुआत में जब वस्तु व्यापार जीडीपी का 16 प्रतिशत था, के विपरीत इस बार व्यापार विखंडन बहुत अधिक महंगा है, और अब यह अनुपात 45 प्रतिशत है। कम व्यापार का अर्थ है ज्ञान का कम प्रसार, जो एकीकरण का एक प्रमुख लाभ है और जिसे सीमा पारीय प्रत्यक्ष निवेश के विखंडन से भी कम किया जा सकता है। व्यापार प्रतिबंधात्मकता को समझने का एक तरीका यह है कि पहले शुरू किए गए व्यापार प्रतिबंधात्मक उपायों की संख्या के अलावा, नए आयात-प्रतिबंधात्मक उपायों के व्यापार कवरेज का आंकलन कियाा जाए [चार्ट V.2][7]।

5 https://www.wto.org/english/news_e/news24_e/trdev_11dec24_e.htm#:~:text=That%20means%20the%20stockpile%20of,or%209.9%25%20of%20world%20imports.

6 'भू-राजनीति और वैश्विक व्यापार और डॉलर पर इसका प्रभाव', स्टैनफोर्ड इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक पॉलिसी रिसर्च में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा प्रणाली (आईएमएस) के भविष्य पर श्रृंखला में गीता गोपीनाथ (आईएमएफ एफडीएमडी) द्वारा दिया गया व्याख्यान, 7 मई, 2024

7 https://www.wto.org/english/news_e/news24_e/trdev_11dec24_e.htm

चार्ट V.2: नए आयात-प्रतिबंधात्मक उपायों का व्यापार कवरेज (बिलियन अमरीकी डॉलर, असंचयी)

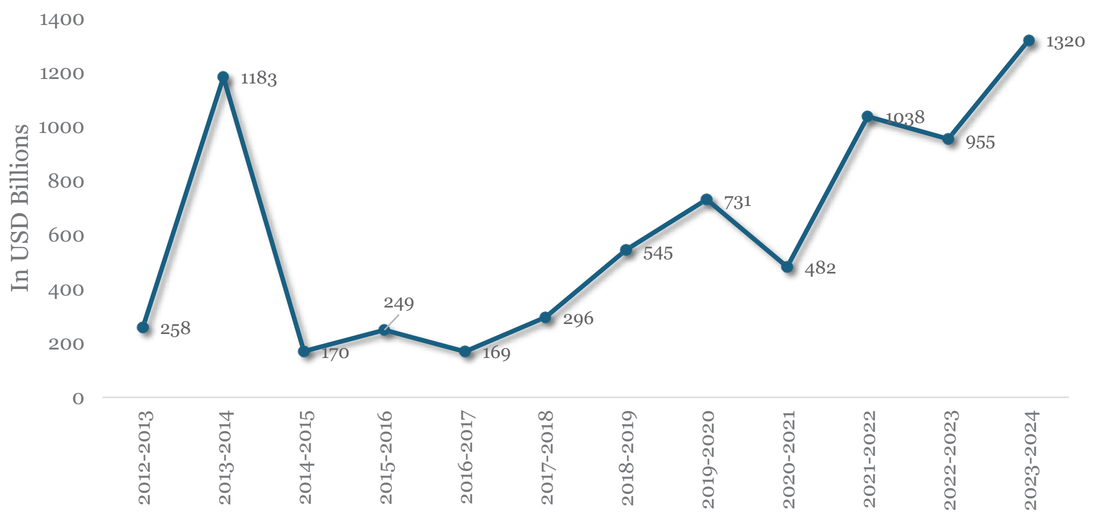

स्रोत: व्यापार नीति समीक्षा निकाय (टीपीआरबी) को प्रस्तुत डब्ल्यूटीओ व्यापार समीक्षा रिपोर्ट; दिसंबर 2024

5.14 जीईएफ का प्रभाव वैश्विक एफडीआई प्रवाह में देखा जा रहा है, जो भू-राजनीतिक रूप से संरेखित देशों, विशेष रूप से कार्यनीतिक क्षेत्रों में केंद्रित हो रहा है। एफडीआई के इस अंतरण से कई उभरते बाजारों और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं की संवेदनशीलता बढ़ जाती है। फ्रेंड शोरिंग और री-शोरिंग से उत्पन्न होने वाले इस एफडीआई अंतरण से जुड़े परिणामी नुकसान विशेष रूप से उभरते बाजारों और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के लिए गंभीर हैं। उन्हें उन्नत अर्थव्यवस्थाओं की ओर से लगाए जाने वाले कड़े प्रतिबंधों का सामना करना पड़ता है, जो उनके एफडीआई के प्रमुख स्रोत हैं[8]।

5.15 आधारित अवधारणाओं के आधार पर, यह अनुमान लगाया गया है कि व्यापार विखंडन से वैश्विक उत्पादन की लागत 0.2 प्रतिशत (सीमित विखंडन/निम्न लागत समायोजन परिदृश्य में) से लेकर जीडीपी के 7% (उच्च विखंडन/उच्च लागत समायोजन परिदृश्य में) तक हो सकती है। जब हम मिश्रण में संभावित तकनीकी वियोजन को जोड़ते हैं तो उत्पादन हानि का अनुमान चुनिंदा देशों में जीडीपी के 8-12% तक अधिक होता है। इस तरह के परिणाम का व्यापक प्रभाव यह होगा कि जैसे-जैसे वैश्विक अर्थव्यवस्था की गति धीमी होती जाएगी, वैश्विक पूंजी सतत विकास वाली अर्थव्यवस्थाओं की तलाश करती है।

8 https://www.elibrary.imf.org/display/book/9798400224119/CH004.xml#:~:text=The%20recent%20slowdown%20in%20FDI,structural%20reforms%20and%20improving%20infrastructure.

स्पष्ट अंतर्निहित समस्या

5.16 व्यापार और निवेश संबंधी प्रतिबंधों के बढ़ने के साथ वैश्विक आर्थिक जुड़ाव में मौलिक परिवर्तन हो रहे हैं। वर्ष 2020 और वर्ष 2023 के बीच, वैश्विक स्तर पर व्यापार और निवेश से संबंधित 22000 से अधिक नए प्रतिबंध लागू हुए हैं [चार्ट V.3]। वैश्विक संरचनात्मक शक्तियों में इस परिवर्तन का प्रभाव वैश्विक व्यापार वृद्धि में दिखाई देता है, जिसमें काफी कमी आई है, और वैश्विक अर्थव्यवस्था में दीर्घकालिक स्थिरता के संकेत दिखाई देने लगे हैं [चार्ट V.4]। इस दस्तावेज की प्रस्तावना में भारत की विकास संभावनाओं के लिए प्रतिकूल वैश्विक पृष्ठभूमि का भी व्यापक रूप से उल्लेख किया गया है।

चार्ट V.3: व्यापार और निवेश संबंधी प्रतिबंधों का विस्तार

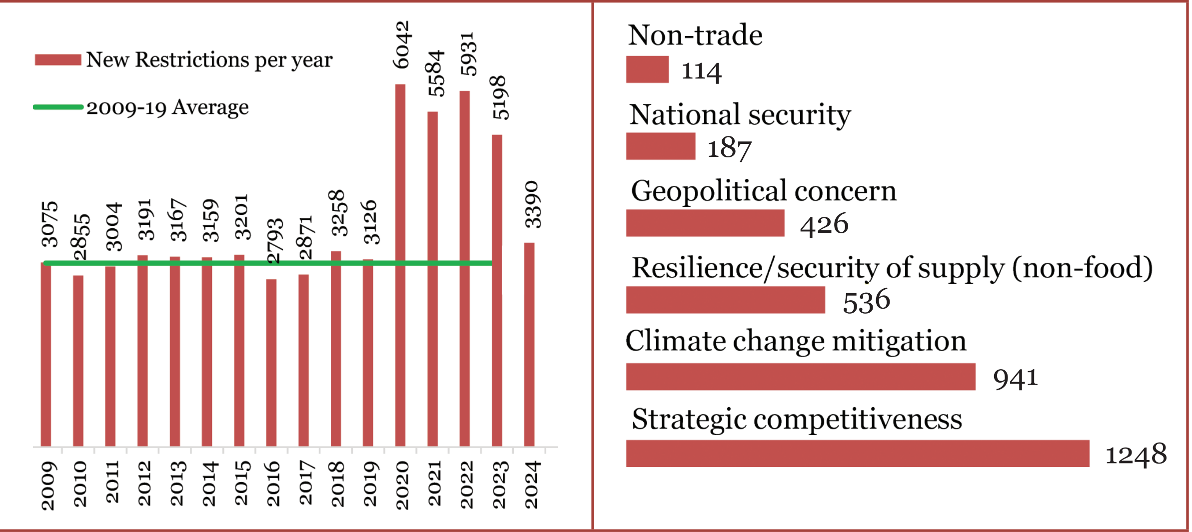

ग्लोबल ट्रेड अलर्ट डेटा

चार्ट V.4: वैश्विक संरचनात्मक शक्तियों में परिवर्तन

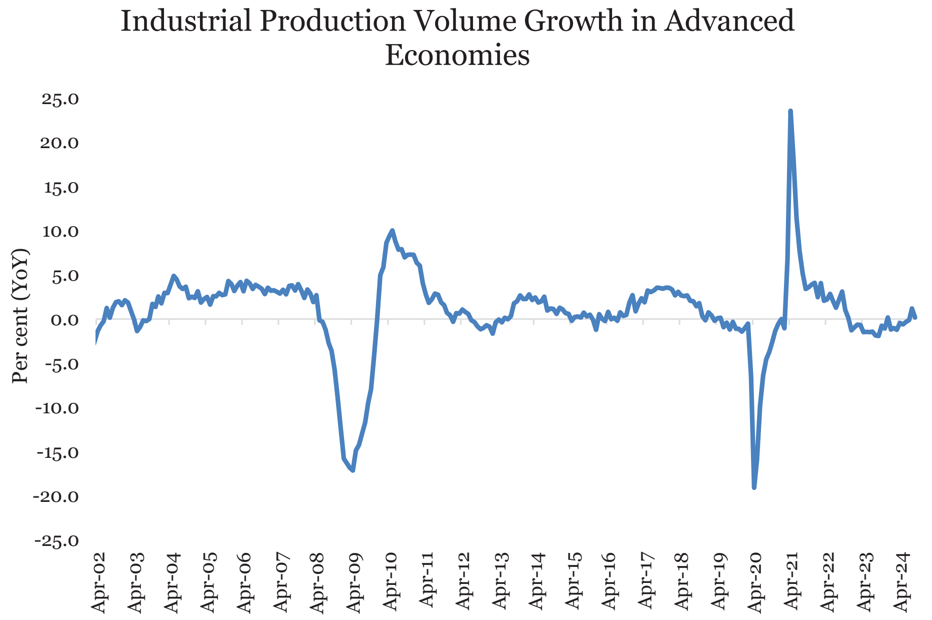

स्रोतः वर्ल्ड ट्रेड मॉनिटर

5.17 वैश्विक अर्थव्यवस्था एक महत्वपूर्ण मोड़ पर है, जहाँ लंबे समय से चले आ रहे सिद्धांतों और पद्धतियों का पुनर्मूल्यांकन किया जा रहा है और कुछ मामलों में, वे अपनी प्रासंगिकता खो रहे हैं। इस परिवर्तन में वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में चीन की प्रमुख भूमिका भी शामिल है, जो आर्थिक परिदृश्य को नया आकार दे रही है। परिणामस्वरूप, कई देश अब ऐसे माहौल में काम कर रहे हैं, जो उनके पहले के माहौल से बिल्कुल अलग है, जहाँ पारंपरिक नियमों पर पुनर्विचार किया जा रहा है और इस बात को लेकर अनिश्चितता है कि उनकी जगह कौन लेगा।

5.18 चीन वैश्विक विनिर्माण और ऊर्जा संचरण परितंत्र में एक प्रमुख शक्ति है। उसने मुख्य संसाधनों जिन्हें आज वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं हेतु महत्वपूर्ण माना जाता है, तक पहुंच और उन पर नियंत्रण करने के लिए अपनी प्रतिस्पर्धात्मकता और आर्थिक नीति का लाभ उठाते हुए रणनीतिक लाभ प्राप्त किया है। "*वर्ष 2000 में, एशिया, यूरोप और लैटिन अमेरिका में संयुक्त राज्य अमेरिका और उसके सहयोगियों ने वैश्विक औद्योगिक उत्पादन में अधिक हिस्सेदारी प्राप्त की, जबकि दो दशकों के त्वरित विकास के बाद भी, चीन की हिस्सेदारी सिर्फ 6% थी। सिर्फ तीस साल बाद, यूएनआईडीओ का अनुमान है कि चीन वैश्विक विनिर्माण में 45% हिस्सेदारी प्राप्त करेगा, जो अकेले ही अमेरिका और उसके सहयोगियों से बराबरी कर लेगा या उनसे आगे निकल जाएगा। यह किसी एक देश द्वारा विनिर्माण में प्रभुत्व प्राप्त करने का ऐसा स्तर है जो विश्व इतिहास में पहले सिर्फ दो बार देखा गया है अर्थात – औद्योगिक क्रांति की शुरुआत में ब्रिटेन द्वारा और दूसरे विश्व युद्ध के ठीक बाद अमेरिका द्वारा। इसका अर्थ यह है कि उत्पादन के एक विस्तारित युद्ध में, इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि पूरा विश्व एकजुट होकर अकेले चीन को हरा सकता है*" (चार्ट V.5)[9],[10]।

9 यूएनआईडीओ नेशनल अकाउंट डाटाबेस; https://stat.unido.org/data/table\dataset=national&accounts.

10 नोअह स्मिथ, 'मैन्युफैक्चरिंग इज ए वार नाउ', 4 दिसंबर, 2024 (https://www.noahpinion.blog/p/manufacturing-is-a-war-now).

चार्ट V.5: वैश्विक औद्योगिक उत्पादन की बदलती संरचना

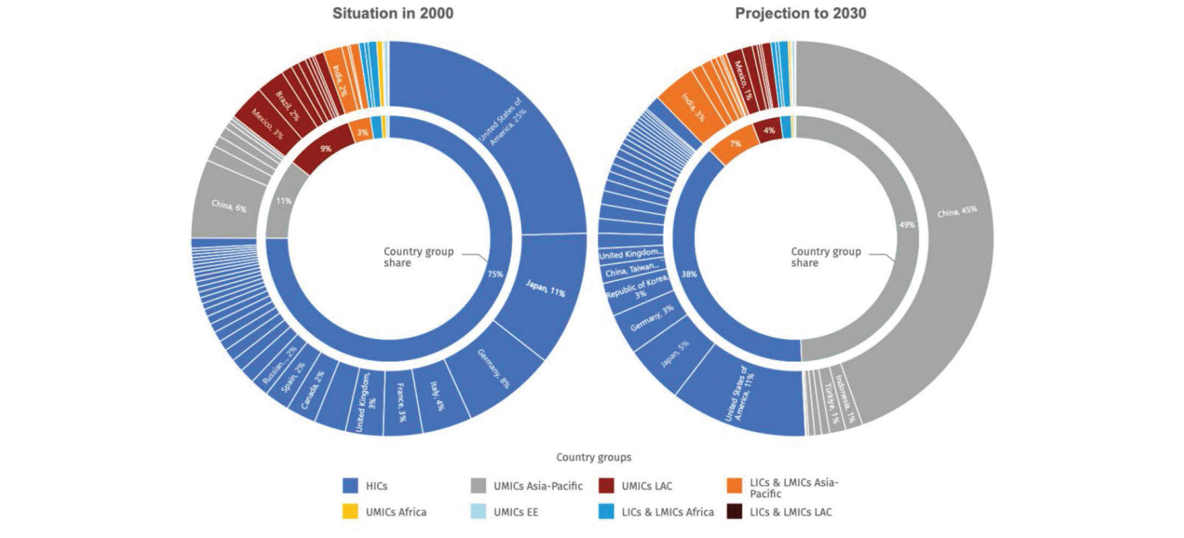

स्रोत: यूएनआईडीओ राष्ट्रीय लेखा डेटाबेस पर आधारित यूएनआईडीओ की व्याख्या

नोट: वर्ष 2030 तक यूएनआईडीओ के अनुमान ऐतिहासिक औसत वार्षिक वृद्धि दर (2010 और 2019 के बीच) पर आधारित हैं और 2030 तक नवीनतम उपलब्ध अवलोकनों (2024) पर लागू होते हैं। एलआईसी = कम आय वाले देश; एलएमआईसी – निम्न मध्यम आय वाले देश; युएमआईसी – उच्च मध्यम आय वाले देश; एचआईसी – उच्च आय वाले देश; ईई – पूर्वी यूरोप; एलएसी – लैटिन अमेरिका और कैरिबियन

5.19 विनिर्माण क्षेत्र की बड़ी कंपनी के रूप में चीन के विकास का प्रभाव ऑटोमोबाइल (विशेषकर इलेक्ट्रिक वाहन) विनिर्माण, महत्वपूर्ण खनिजों (तांबा, लिथियम, निकल, कोबाल्ट, ग्रेफाइट आदि) के खनन तथा शोधन क्षमता और स्वच्छ ऊर्जा उपकरण आदि में देखा जा सकता है। वैश्विक ऑटो बाजार में चीन के विकास ने जर्मनी और जापान जैसी अर्थव्यवस्थाओं में दीर्घकालिक प्रतिद्वंद्वियों के व्यापार को बाधित कर दिया है और यह महत्वपूर्ण खनिजों और अन्य आर्थिक संसाधनों के वैश्विक वितरण पर प्रभुत्व है, जिससे भावी पीढ़ियों के लिए संभावित निर्भरताएं सृजित हो रही हैं। चीन के पुनरुत्थान की भविष्यवाणी 1904 में ब्रिटिश भूगोलवेत्ता और राजनयिक हैलफोर्ड मैकिंडर[11] ने की थी। इन विकास क्रमों के परिणामस्वरूप विश्व द्वारा चीन को विनिर्माण संबंधी कार्य आउटसोर्स करने की कार्यप्रणाली जो वैश्विकरण के युग में तेजी से अपनाई गई है, पुनर्स्थापित होने के लिए तैयार है।

जलवायु परिवर्तन, चीन और भू-राजनीति

5.20 जलवायु वैश्विक स्तर पर सभी के लिए समान रूप से उपलब्ध है। यह सभी को, हर जगह इस ढंग से प्रभावित करती है जिनकी अभी भी जांच की जा रही है और इसकी समझ विकसित की जा रही है। एडवर्ड एन. लोरेंज ने 1972 के अपने शोधपत्र '*डज दा फ्लैप ऑफ अ बटरफ्लाइज विंग्स इन ब्राजील सेट ऑफ अ टारनेडो इन टेक्सास' में जिज्ञासा जाहिर की*[12]? यह शायद अब पहले से कहीं ज्यादा सच है।

5.21 जलवायु परिवर्तन का आर्थिक प्रभाव अच्छी तरह से प्रलेखित है। जलवायु परिवर्तन की प्रत्यक्ष

11 https://www.bloomberg.com/opinion/features/2025-01-05/halford-mackinder-predicted-today-s-world-over-a-century-ago

12 पूर्वानुमान: क्या ब्राजील में लिए गए छोटे से छोटे निर्णय का असर टेक्सास पर पड़ता है? (लोरेंज, 1972)

लागत ने प्रमुख शिक्षाविदों का ध्यान आकर्षित किया है[13]। अध्ययनों ने मात्रा निर्धारित की है कि 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि वैश्विक जीडीपी को 12% तक कम करती है और वैश्विक तापमान चरम जलवायु घटनाओं के साथ एक मजबूत संबंध दर्शाता है। वर्ष 1960 से 2019 की अवधि में जलवायु परिवर्तन के साथ और बिना जलवायु परिवर्तन के मॉडल पर आधारित उत्पादन विकास दर चित्र 7 में दर्शाई गई है (बिलाल, केनजिग; 2024)[14]।

चार्ट V.6: जलवायु परिवर्तन के साथ विकास का लेखा-जोखा

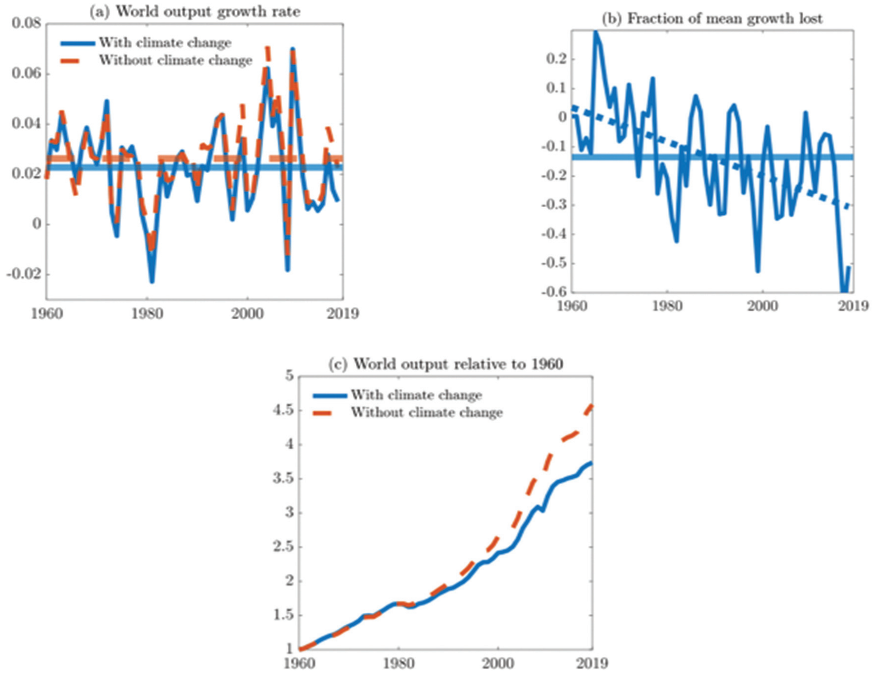

स्रोत: बिलाल, केन्जिग; 2024

पैनल (क): जलवायु परिवर्तन के साथ (गहरा नीला) और बिना (डैश लाल) विश्व उत्पादन वृद्धि दर। क्षैतिज रेखाएँ: नमूना औसत।

पैनल (ख): जलवायु परिवर्तन के कारण विकास दर में कमी का अंश (1960-2019 के औसत से वार्षिक वृद्धि हानि)। क्षैतिज रेखा: नमूना औसत। डैश रेखा: रैखिक प्रतिगमन फिट।

पैनल (ग): जलवायु परिवर्तन के साथ (गहरा नीला) और बिना (डैश नारंगी) विश्व उत्पादन, 1960 में सामान्यीकृत।

5.22 चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय संघ और अन्य जी 7 अर्थव्यवस्थाएं वैश्विक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन का 50 प्रतिशत से अधिक उत्पादन करती हैं। सभी देशों ने वर्ष 2050 तक निवल-शून्य उत्सर्जन प्राप्ति के लिए लक्ष्य रखा है। ये अर्थव्यवस्थाएँ पर्यावरणीय वस्तुओं और प्रौद्योगिकियों के व्यापार में नवीकरणीय ऊर्जा के विकास और उत्सर्जन को कम करने के लिए एक दूसरे पर बहुत अधिक निर्भर हैं। इसलिए, इन अर्थव्यवस्थाओं के बीच व्यापारिक अवरोध हरित ऊर्जा संचरण के लिए महत्वपूर्ण जोखिम उत्पन्न करेंगे, जिससे वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भारी लागत आएगी।

5.23 भारत के लिए, पांच प्रमुख तत्व जलवायु कार्रवाई (पंचामृत)[15] के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाती है। यह भारत के उत्पादन, प्रापण और अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के तरीके को महत्वपूर्ण

13 जलवायु परिवर्तन का व्यापक आर्थिक प्रभाव: वैश्विक बनाम स्थानीय तापमान (बिलाल, केन्जिग; 2024)

14 https://www.nber.org/system/files/working_papers/w32450/w32450.pdf

15 https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1795071

रूप से प्रभावित करेगा और इस परिवर्तन के लिए हमारे ऊर्जा मिश्रण में [वर्ष 2020 की तुलना में][16] परिवर्तन की आवश्यकता होगी। वर्ष 2030 में संस्थापित क्षमता के अनुमान से पता चलता है कि संस्थापित क्षमता में नवीकरणीय ऊर्जा, विशेष रूप से सौर और पवन ऊर्जा की हिस्सेदारी में काफी वृद्धि होने की संभावना है। इसके विपरीत, कोयला और लिग्नाइट की हिस्सेदारी में तेजी से गिरावट आने की संभावना है [चार्ट V7,8]।

5.24 चूंकि विश्व एक बार फिर जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से जूझ रहा है, इसलिए ऊर्जा संचरण का मार्ग चीन से शुरू होता है।

5.25 पिछले दशक में, वैश्विक सौर फोटोवोल्टिक सेल (पीवी) विनिर्माण क्षमता तेजी से यूरोप, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका से चीन में स्थानांतरित हो गई है, जिसने नई पीवी आपूर्ति क्षमता में 50 बिलियन अमरीकी डालर से अधिक का निवेश किया है–जो यूरोप की तुलना में दस गुना अधिक है[17]। पर्यावरणीय वस्तुओं के क्षेत्र में चीन के प्रभुत्व पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए। सौर पैनलों (पॉलीसिलिकॉन, इनगॉट्स, वेफर्स, सेल और मॉड्यूल) में चीन की हिस्सेदारी सभी विनिर्माण क्षेत्रों में 80 प्रतिशत से अधिक है। दिलचस्प बात यह है कि यह वैश्विक पीवी मांग में चीन की हिस्सेदारी के दोगुने से भी अधिक है। वर्ष 2010 से वर्ष 2021 तक विभिन्न सौर पीवी घटकों के विनिर्माण में चीन की हिस्सेदारी नीचे दी गई है (चार्ट 9,10)। इसके अलावा, यह देश सौर पीवी विनिर्माण उपकरणों[18] के दुनिया के शीर्ष 10 आपूर्तिकर्ताओं का केंद्र है। हालांकि यह दुनिया भर में सौर पीवी उपकरणों की लागत को कम करने में प्रमुख कारक रहा है, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में भौगोलिक संकेद्रण का स्तर भी आपूर्ति में व्यवधान जोखिम उत्पन्न करता है जिसे ध्यान में रखा जाना चाहिए।

चार्ट V.7: भारत की संस्थापित क्षमता मिश्रण [2022 बनाम 2030]

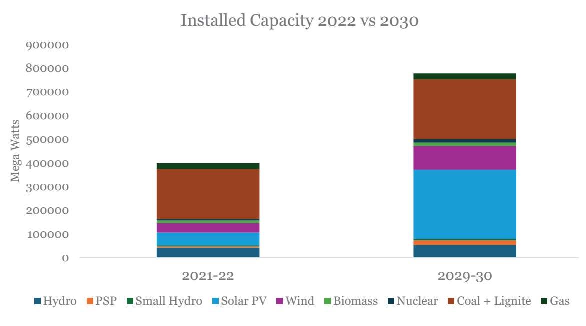

चार्ट V.8: विद्युत उत्पादन के हिस्से में परिवर्तन

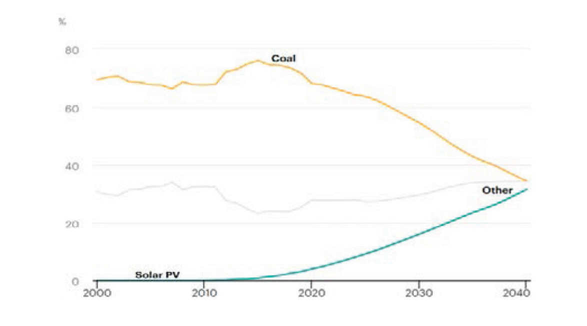

स्रोतः इष्टतम उत्पादन मिश्रण 2020 संस्करण 2.0 पर रिपोर्ट, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण, विद्युत मंत्रालय

16 इष्टतम उत्पादन मिश्रण 2020 संस्करण 2.0 पर रिपोर्ट, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण, विद्युत मंत्रालय
17 अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी; सोलर पीवी ग्लोबल सप्लाई चेन पर विशेष रिपोर्ट (2022)
18 https://www.iea.org/reports/solar-pv-global-supply-chains/executive-summary

चार्ट V.9: देश और क्षेत्र के अनुसार सौर पीवी विनिर्माण, 2010	**चार्ट V.10: देश और क्षेत्र के अनुसार सौर पीवी क्षमता, 2021**
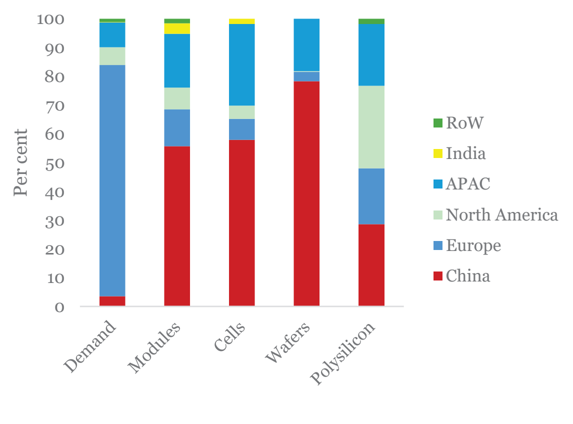	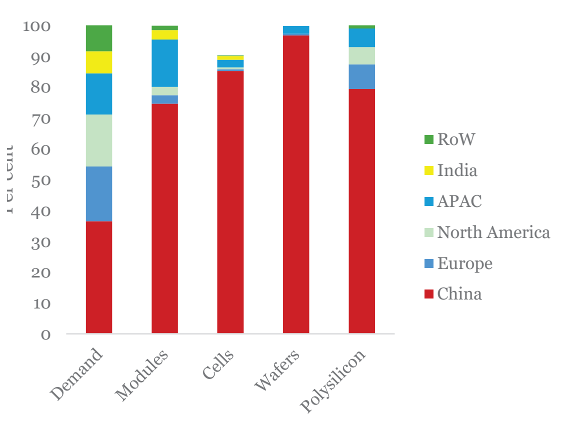

स्रोत: अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी

5.26 दुनिया की संस्थापित पवन ऊर्जा क्षमता का लगभग 60 प्रतिशत चीन से प्राप्त होता है। चीन में दुनिया की बैटरी विनिर्माण क्षमता का लगभग 80 प्रतिशत हिस्सेदारी है, जो ऊर्जा संचरण के लिए महत्वपूर्ण है[19]। सिर्फ वर्ष 2022 में, चीन ने इन क्षेत्रों में अमेरिका और यूरोपीय संघ के निवेश की तुलना में सौर और पवन ऊर्जा, इलेक्ट्रिक वाहनों और बैटरी प्रौद्योगिकियों में विभिन्न निवेशों के लिए 546 बिलियन डॉलर आवंटित किए, जो एक ही वर्ष में 321 बिलियन डॉलर थे[20]।

5.27 जहां तक ऊर्जा की बात है, चीन प्राथमिक सामग्री, विनिर्माण, संस्थापित क्षमता और पुनर्चक्रण क्षमता की आपूर्ति को नियंत्रित करता है और पीवी के कम से कम 80 प्रतिशत मुख्य घटकों का उत्पादन करता है[21]। खनन से लेकर ईवी विनिर्माण तक पूरी इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) आपूर्ति श्रृंखला में चीन के ऊर्ध्वाधर एकीकरण ने उसे इस क्षेत्र में अपना वैश्विक प्रभुत्व बनाए रखने में सक्षम बनाया है। यह भी ध्यान देने योग्य है कि दुनिया के दुर्लभ भू-खनिजों में से लगभग 70 प्रतिशत, जो उच्च भंडारण बैटरी के लिए महत्वपूर्ण संसाधन हैं, चीनी कंपनियों द्वारा प्रसंस्कृत किए जाते हैं[22] (बॉक्स V.1 में देखें।)

बॉक्स V.1: इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए आपूर्ति श्रृंखला संबंधी विचार

सड़क परिवहन संबंधी उत्सर्जन, जो परिवहन क्षेत्र से होने वाले उत्सर्जन का लगभग 75 प्रतिशत है,[23] को कम करना भारत के लिए 2070 तक अपने निवल शून्य लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण है। भारत के निवल शून्य के मार्ग में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी एक महत्वपूर्ण घटक है। भारत ने इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी)

19 https://www.visualcapitalist.com/chinas-dominance-in-battery-manufacturing/

20 https://www.atlanticcouncil.org/blogs/econographics/geoeconomic-fragmentation-is-threatening-the-greenenergytransition/#:~:text=The%20Chinese%20supply%20chain%20for,electric%20vehicles%2C%20and%20battery%20technologies.

21 https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2772737824000208

22 https://www.goldmansachs.com/insights/articles/resource-realism-the-geopolitics-of-critical-mineral-supply-chains

23 रिची, एच., और रोजर, एम. (2024): "कार्स, प्लेंस, प्लेंस, ट्रेंस: व्हेयर डू सीओ2 इमिशन फ्रॉम ट्रांसपोर्ट कम फ्रॉम?" आवर वर्ल्ड इन डेटा https://ourworldindata.org/co2-emissions-from-transport

के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने में महत्वूपर्ण प्रगति की है। तथापि, विकास की गति को बनाए रखने के लिए, कुछ महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखना होगा। उदाहरण के लिए, एक पारंपरिक कार की तुलना में इलेक्ट्रिक वाहन के विनिर्माण[24] के लिए लगभग 6 गुना अधिक खनिजों की आवश्यकता होती है, जिनमें से अधिकांश का उपयोग ईवी बैटरी के उत्पादन में किया जाता है। यह एक महत्वपूर्ण विचार है क्योंकि ईवी के विनिर्माण के लिए महत्वपूर्ण कई खनिज भारत में मुश्किल से उपलब्ध हैं या प्रसंस्कृत किए जाते हैं जबकि, इसके साथ-साथ ये बहुत कम देशों में संकेंद्रित हैं। खान मंत्रालय ने भारत की आर्थिक सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण 33 महत्वपूर्ण खनिजों का विश्लेषण किया है और पाया है कि 24 खनिज वर्तमान में आपूर्ति व्यवधान[25] के उच्च जोखिम में हैं।

चीन की वैश्विक स्तर पर महत्वपूर्ण खनिज प्रसंस्करण और उत्पादन में अत्यधिक हिस्सेदारी है। निकेल, कोबाल्ट और लिथियम जैसी प्रमुख वस्तुओं में, चीन अकेले वैश्विक उत्पादन का क्रमशः 65 प्रतिशत, 68 प्रतिशत और 60 प्रतिशत प्रसंस्करण करने के लिए जिम्मेदार है।[26] इसी तरह, पृथ्वी के दुर्लभ खनिजों के मामले में, चीन वैश्विक खनन में 63 प्रतिशत और वैश्विक प्रसंस्करण उत्पादन में 90 प्रतिशत का योगदान देता है। इसके अलावा, लिथियम-आयन बैटरी का कुछ समय के लिए अन्य प्रौद्योगिकियों पर प्रभाव बना रहेगा, और उनकी मांग 2030[27] तक 23 प्रतिशत की सीएजीआर से बढ़ने की उम्मीद है। व्यवहार्य वैकल्पिक बैटरी प्रौद्योगिकियों की कमी लिथियम-आयन बैटरी में चीन की प्रमुख स्थिति को मजबूत करती है।

सड़क परिवहन को डीकार्बोनाइज करने के भारत के विजन संबंधी कार्य के साथ-साथ फेम (एफएएमई) इंडिया, ऑटो कंपोनेंट्स के लिए उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना और भारत में इलेक्ट्रिक पैसेंजर कारों के विनिर्माण को बढ़ावा देने की योजना (एसपीएमईपीसीआई) जैसी योजनाओं द्वारा सुगम घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। ये योजनाएं घरेलू आपूर्ति श्रृंखलाओं के निर्माण की आवश्यकता के प्रति भारत सरकार की जागरूकता को प्रदर्शित करती हैं। ये अच्छे आधार हैं। भविष्य की नीतियों को अपने कवरेज के दायरे को इस तरह व्यापक बनाना होगा जो ईवी उद्योग की बढ़ती जरूरतों के अनुकूल हो। चूंकि इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग बढ़ने की उम्मीद है, इसलिए डीसी मोटर, ई-मोटर मैग्नेट और अन्य इलेक्ट्रिकल पुर्जों जैसे आयातित घटकों पर निर्भरता बढ़ने[28] की संभावना है। अग्रणी ईवी विनिर्माताओं ने यह पाया है कि अपने कुल सामग्रीगत व्यय में चीन से आयातित सामग्रियों का अनुपात बढ़ रहा है, जो कुछ संसाधनों और तकनीकी जानकारी के संबंध में चीन पर काफी अधिक निर्भरता को दर्शाता है।[29]

ऐसे जोखिमों से निपटने के लिए एडवांस्ड केमिस्ट्री सेल मैन्युफैक्चरिंग हेतु पीएलआई योजना और खानजी बिदेश इंडिया लिमिटेड (केएबीआईएल) की स्थापना जैसी पहलें की गई हैं। इसके अतिरिक्त, इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए नीतियों को सोडियम-आयन और सॉलिड-स्टेट बैटरी जैसी उन्नत बैटरी प्रौद्योगिकियों में अधिक आरएंडडी द्वारा संचालित और अधिक आत्मनिर्भर इको-सिस्टम को बढ़ावा देकर आपूर्ति श्रृंखलाओं को जोखिम मुक्त करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इस क्षेत्र में बौद्धिक संपदा को सुरक्षित करना अमूल्य

24 आईईए (2021): "मिनिरल्स यूज्ड इन इलेक्ट्रीक कार्स कंपेयर्ड टू कंवेंशनल कार्स – चार्ट – डेटा एंड स्टैटिक्स", अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी। https://www.iea.org/data-and-statistics/charts/minerals-used-in-electric-cars-compared-to-conventional-cars

25 खान मंत्रालय। (2023): "भारत के महत्वपूर्ण खनिज", रिपोर्ट ऑफ द कमेटी ऑन आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रिटिकल मिनिरल्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया

26 रिसोर्स रियलिज्मः द जियोपॉलिटिक्स ऑफ क्रिटिकल मिनिरल्स सप्लाई चौन्स, गोल्डमैन सैक्स रिसर्च, सितंबर 2023

27 नेविगेटिंग द ईवी बैटरी इकोसिस्टम। बैन एंड कंपनी।

28 भारत इलेक्ट्रिक वाहन रिपोर्ट 2023. बैन एंड कंपनी

29 https://www.outlookbusiness.com/explainers/india-incs-ev-play-continues-to-face-the-chinese-dilemma.

साबित हो सकता है। इसके अतिरिक्त, बैटरी रीसाइक्लिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश को सुविधाजनक बनाने से भारतीय ऑटोमोटिव क्षेत्र को अधिक दीर्घकालिक लाभ मिल सकता है। इस बीच, पीएलआई योजनाएँ ईवी सेल (लिथियम-आयन सेल) के निर्माण को भी प्रोत्साहित कर सकती हैं, क्योंकि अधिकांश विनिर्माण और मूल्य संवर्धन सेल-निर्माण चरण तक होता है। इसके अलावा, भारत को अन्य देशों के साथ प्रौद्योगिकी हस्तांतरण समझौते स्थापित करने का लक्ष्य रखना चाहिए जो अपनी आपूर्ति श्रृंखलाओं में भी विविधता लाना चाहते हैं। अन्य महत्वाकांक्षी देशों के साथ साझेदारी वैश्विक बाजार में तुलनात्मक लाभ हासिल करने की उच्च लागत को वितरित करने में मदद कर सकती है।

5.28 सार्वजनिक परिवहन नेटवर्क का विस्तार विदेशी आपूर्ति श्रृंखलाओं पर निर्भरता को कम करने का एक और तरीका है जो ई-मोबिलिटी के लिए आवश्यक है और आने वाले कुछ समय के लिए आवश्यक होगा। भारतीय शहर मेट्रो रेल नेटवर्क में भारी निवेश कर रहे हैं ख्र और यह सही भी है - तथा अपने दायरे का विस्तार कर रहे हैं। ब्राजील और चीन में, 50 प्रतिशत से अधिक शहरी निवासियों को बड़े पैमाने पर पारगमन के लिए सुविधाजनक पहुंच प्राप्त है। हालांकि, भारत में केवल 37 प्रतिशत शहरी निवासियों के पास सार्वजनिक परिवहन की आसान पहुंच है। अन्य देशों की सफलता की प्रतिकृति करने के लिए, भारत को एकीकृत परिवहन प्रणालियों को विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जो बसों, मेट्रो रेलों और पारगमन के अन्य साधनों को कुशलता से जोड़ते हैं। सार्वजनिक परिवहन को अधिक कुशल, विश्वसनीय, आरामदायक, सुलभ और सुरक्षित बनाने में निवेश करना भी आयात पर हमारी निर्भरता को कम करते हुए निवल शून्य संबंधी लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। इसके अलावा, एक मजबूत सार्वजनिक परिवहन प्रणाली यातायात की भीड़ को कम करने, ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने और यह सुनिश्चित करने में भी मदद करेगी कि स्वच्छ मोबिलिटी के लाभ निजी ई-मोबिलिटी समाधानों के विपरीत, सभी सामाजिक-आर्थिक समूहों के लिए सुलभ हो, जिससे एक अधिक समुत्थानशील और न्यायसंगत ऊर्जा संचरण को बढ़ावा मिलेगा।

5.29 इस बात पर बल दिया जा सकता है कि भारत ने उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना जैसी पहलों के माध्यम से नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने और नवीकरणीय ऊर्जा उपकरणों के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण प्रगति की है। पीएलआई योजना का उद्देश्य घरेलू निर्माताओं को प्रोत्साहन देकर सौर पैनलों, पवन टर्बाइनों और बैटरी भंडारण सहित प्रमुख क्षेत्रों में भारत की विनिर्माण क्षमताओं को बढ़ाना है। पीएलआई योजना के तहत घरेलू विनिर्माण प्रयासों से लागत में कमी, ऊर्जा सुरक्षा में सुधार और रोजगार को बढ़ावा देकर भारत के नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्यों को महत्वपूर्ण रूप से सहायता मिलने की उम्मीद है। घरेलू क्षमताओं का विनिर्माण किया जा रहा है। अभी के लिए, भारत 75 प्रतिशत लिथियम-आयन बैटरियां चीन से आयात करता हैं, और इसमें पॉलीसिलिकॉन, इनगॉट्स और वेफर्स जैसे प्रमुख घटकों के लिए उत्पादन क्षमता लगभग न के बराबर है।

5.30 काल्पनिक परिदृश्य में, आईएमएफ यह दर्शाता है कि जहां ब्लॉकों के बीच महत्वपूर्ण खनिजों का व्यापार बाधित है, नवीकरणीय ऊर्जा और इलेक्ट्रिक वाहनों में निवेश वर्ष 2030 तक अविभाजित विश्व की तुलना में 30 प्रतिशत तक निवेश कम हो सकता है[30]। भू-आर्थिक विखंडन की प्रकृति और खतरा इस

30 https://www.imf.org/en/Blogs/Articles/2023/10/03/geoeconomic-fragmentation-threatens-food-security-and-clean-energy-transition

तथ्य से बढ़ जाता है कि बहुपक्षवाद के सिद्धांतों की रक्षा करने वाले आधारभूत संस्थागत ढांचे भी स्वयं को एक निर्णायक मोड़ पर पाते हैं। इस वैश्विक पृष्ठभूमि से, हम इस बात की ओर रुख कर सकते हैं कि भारत अपने विकास और विकास के लक्ष्यों को कैसे प्राप्त करेगा।

भारत की विकास संभावनाओं के निहितार्थ

5.31 विकसित भारत@2047 का विजन वर्ष 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र के रूप में देखना है, जो हमारी स्वतंत्रता का शताब्दी वर्ष होगा[31]। इससे कम से कम एक दशक तक प्रत्येक वर्ष लगभग 8 प्रतिशत की निरंतर आर्थिक वृद्धि होगी। इस वृद्धि को प्राप्त करने के लिए, निवेश दर को सकल घरेलू उत्पाद के लगभग 35 प्रतिशत तक बढ़ाना होगा, जो वर्तमान में 31 प्रतिशत है। इसके अतिरिक्त, विनिर्माण क्षेत्र को और विकसित करना और एआई, रोबोटिक्स और जैव प्रौद्योगिकी जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों में निवेश करना आवश्यक होगा। भारत को वर्ष 2030[32] तक सालाना 78.5 लाख नए गैर-कृषि संबंधी रोजगार सृजन करने, 100 प्रतिशत साक्षरता प्राप्त करने, हमारे शिक्षा संस्थानों की गुणवत्ता विकसित करने और उच्च गुणवत्ता, भविष्य के लिए तैयार अवसंरचना को बड़े पैमाने पर और गति से विकसित करने की आवश्यकता होगी।

5.32 भारत ने पिछले दशक में कई संरचनात्मक सुधार किए हैं। माल एवं सेवा कर, जिसे वास्तव में इंडियंस ई यू मोमेंट के रूप में वर्णित किया गया है, से लेकर दिवाला और दिवालियापन संहिता, जिसने कॉर्पोरेट नवीकरण से निपटने के लिए फ्रेमवर्क स्थापित करने से लेकर रेरा (रियल एस्टेट विनियमन अधिनियम) तक, जिसने रियल एस्टेट क्षेत्र को साफ करने और डिजिटल अवसंरचना-इंडिया स्टैक (यूआईडी, यूपीआई, डीबीटी) के तेजी से शुरूआत करने में मदद की। जुलाई 2017 में जीएसटी की शुरुआत ने भारत के अप्रत्यक्ष कर ढांचे में एक महत्वपूर्ण बदलाव किया है, जिसका उद्देश्य पूरे देश में एकीकृत, सुव्यवस्थित कराधान प्रणाली तैयार करना था।

5.33 माल एवं सेवा कर (जीएसटी) जीएसटी के कार्यान्वयन ने व्यापारिक सुगमता में वृद्धि, डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने, एकल बाजार के विनिर्माण के माध्यम से आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा देने और राजस्व सृजन तथा संग्रहण में वृद्धि के माध्यम से कई सकारात्मक बातें उभरकर सामने आई है। इसी तरह, आईबीसी ने बैंकों में गैर-निष्पादित आस्तियों (एनपीए) का तेजी से समाधान किया है और एक अधिक कुशल दिवालियापन प्रक्रिया तैयार की है, जिससे निवेशकों का विश्वास बढ़ा है और भारत का डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (डीपीआई) अधिक समावेशी और कुशल अर्थव्यवस्था की दिशा में देश की यात्रा में एक गेम-चेंजर के रूप में उभरा है। डिजिटल उपकरणों और प्लेटफार्मों का लाभ उठाकर, डीपीआई ने न केवल सेवाओं की पहुंच को बढ़ाया है, बल्कि विभिन्न क्षेत्रों में परिवर्तनकारी लाभ भी पहुंचाया है।

5.34 उपरोक्त के अलावा, भारत आर्थिक विकास, रोजगार सृजन और नवाचार को बढ़ावा देने में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) की महत्वपूर्ण भूमिका को उजागर करता है। सरकार ने एमएसएमई के विकास को सहायता और बढ़ावा देने के लिए पिछले दशक में कई नीतियों और पहलों को कार्यान्वित किया है। ये प्रयास वित्त तक पहुंच में सुधार, तकनीकी क्षमताओं को बढ़ाने, बाजार संपर्क प्रदान करने और एमएसएमई के सामने आने वाली संरचनात्मक चुनौतियों का समाधान करने पर संकेंद्रित थे। तथापि,

31 https://pib.gov.in/PressNoteDetails.aspx?NoteId=153439&ModuleId=3&reg=3&lang=1

32 https://pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=2034952

इन पहलों ने एमएसएमई को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण प्रगति की है, लेकिन विनियामक वातावरण में कतिपय चुनौतियां बनी हुई हैं। विनियामक अनुपालन बोझ औपचारिकरण और श्रम उत्पादकता को रोकता है, रोजगार वृद्धि को सीमित करता है, नवाचार को रोकता है तथा विकास को धीमा करता है।

5.35 भारत में फर्मों की छोटे पैमाने पर बने रहने की प्रवृत्ति देखी गई है। छोटे पैमाने की बनी रहकर वे संस्थागत पूंजी, कुशल प्रतिभा और प्रौद्योगिकी के उपयोग से वंचित हो जाती हैं और अक्सर औपचारिक आपूर्ति श्रृंखलाओं से बाहर काम करती हैं। इससे एक समानांतर अनौपचारिक अर्थव्यवस्था बनती है और इससे श्रम उत्पादकता कम होती है। छोटी कंपनियों के रूप में बने रहने का तर्क विनियामक निगरानी के अंतर्गत रहना और नियमों, श्रम तथा सुरक्षा कानूनों से दूर रहना है। विडंबना यह है कि सबसे बड़ा नुकसान रोजगार सृजन और श्रम कल्याण को होता है, जिसके लिए क्रमश: प्रोत्साहन और रक्षा के लिए अधिकांश नियम मूल रूप से बनाए गए थे।

5.36 इस क्षेत्र में नीतिगत कार्रवाई के माध्यम से प्रोत्साहन के स्वरूपों को आगे बढ़ाने के लिए काफी कुछ किया जा चुका है। समाधान का एक हिस्सा डिजिटलीकरण, गैर-अपराधीकरण और कार्यों का विनिवेश है। पैन 2.0 परियोजना जैसे उपाय कागज रहित प्रक्रियाओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए निर्दिष्ट सरकारी एजेंसियों की सभी डिजिटल प्रणालियों के लिए एक सामान्य पहचानकर्ता के रूप में पैन की स्थापना करना सही दिशा में कदम है[33]। इसी तरह, जन विश्वास अधिनियम, 2023 ने 19 मंत्रालयों/विभागों द्वारा प्रशासित 42 केंद्रीय अधिनियमों में 183 प्रावधानों को गैर-अपराधीकृत कर दिया है[34]। संयुक्त संसदीय समिति ने जन विश्वास विधेयक की समीक्षा की और बाद में इस कार्य को अन्य अधिनियमों तक विस्तारित करने की सिफारिश की, जिससे भारत की नियामक संरचना का निरंतर आधुनिकीकरण सुनिश्चित हो सके - जन विश्वास 2.0[35]। अत: यह सत्य है कि बहुत कुछ किया जा चुका है, और यह भी सत्य है कि दो कारणों से बहुत कुछ किया जाना बाकी है; पहला, हमारा आकार है; दूसरा, जैसे-जैसे अर्थव्यवस्था में बढ़ोत्तरी होती है, वैसे-वैसे, अनदेखी और गैर-बाध्यकारी बाधाएं उभरती है, बाध्यकारी बन जाती है। अत:, विकसित होने की निरंतर आवश्यकता है।

5.37 वित्त वर्ष 2024 के आर्थिक सर्वेक्षण के अध्याय 5 में मध्यावधिक परिप्रेक्ष्य से ध्यान केंद्रित करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में कई संरचनात्मक सुधारों और रणनीतियों की पहचान की गई थी। इनमें घटक निर्माताओं की क्षमता और जानकारी के उन्नयन के लिए एक सक्षम नीति और नियामक वातावरण बनाने, प्रशिक्षित मानव संसाधनों की उपलब्धता बढ़ाने, भारत के सकल स्थिर पूंजी निर्माण में तेजी लाने के लिए संसाधन बाधाओं और नियामक बाधाओं को दूर करने; भारत के मिटलस्टैंड के विकास और विस्तार के लिए एक रणनीति और राज्यों और स्थानीय सरकारों के स्तर पर गैर-विनियमन और नीतिगत कार्रवाइयों के माध्यम से इसे विस्तृत करने में सहायता करने; कृषि क्षेत्र में विकास की बाधाओं को दूर करने में मदद करने वाले सुधार करने; वैश्विक हरित पूंजी हासिल करने के लिए सॉवरेन वेल्थ कोष, वैश्विक पेंशन, निजी इक्विटी और आधारभूत संरचना निधि से वैश्विक हरित पूंजी के तेजी से बढ़ते पूल का लाभ उठाने की रणनीति; शिक्षा-रोजगार के अंतर को पाटने की दिशा में काम करने और नई शिक्षा नीति के उद्देश्य

33 https://pib.gov.in/PressReleseDetailm.aspx?PRID=2077608&reg=3&lang=1

34 https://pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=1945263

35 https://pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=2059868#:~:text=The%20Act%2C%20passed%20by%20the,the%20burden%20on%20the%20judiciary

और क्षमता को साकार करने में सक्षम बनाने; और राज्य की क्षमता और सक्षमता का निर्माण करने से संबंधित सुझाव शामिल था।

5.38 इन संरचनात्मक सुधारों के साथ सफलता प्राप्त करने हेतु, एक बुनियादी पूर्वापेक्षा यह है कि पिछले दस वर्षों में पहले से शुरू किए गए गैर-विनियमन एजेंडे को आगे बढ़ाया जाए, लोगों को उनकी एजेंसी वापस प्रदान की जाए और व्यक्तियों तथा संगठनों को और अधिक आर्थिक स्वतंत्रता प्रदान की जाए। इस प्रस्तावना ने फिर से इसके महत्व को स्पष्ट रूप से रेखांकित किया है।

5.39 इस नई और उभरती वैश्विक वास्तविकता के बीच, इन संरचनात्मक सुधारों के साथ सफल होने का सबसे अच्छा तरीका आंतरिक साधनों और विकास के घरेलू प्रोत्साहकों पर भरोसा करना शुरू करना है, एक केंद्रीय घटक-वैध आर्थिक गतिविधि को आगे बढ़ाने के लिए व्यक्तियों और संगठनों की आर्थिक स्वतंत्रता पर ध्यान केंद्रित करना है। लाइसेंसिंग, निरीक्षण और अनुपालन संबंधी आवश्यकताओं के बोझ से मुक्त, भारत के लोग और छोटे उद्यम, अपनी उच्च आकांक्षाओं और आंतरिक रचनात्मकता के साथ, वृद्धि, रोजगार और विकास की चुनौतियों का हल ढूंढ लेंगे। विगत दस वर्षों में पहले से ही चल रहे गैर-विनियमन एजेंडे में तेजी लाना और बढ़ाना समय की मांग है। साथ ही, देश का प्रत्येक राज्य विभिन्न क्षेत्रों में अन्य राज्यों की सर्वोत्तम पद्धतियों से सीख सकता है ताकि सभी एक साथ प्रगति कर सकें। अगला खंड आगे का रास्ता दिखाता है।

विकास के आंतरिक साधनों को पुनर्जीवित करना-गैर-विनियमन के माध्यम से आर्थिक स्वतंत्रता को बढ़ाना

5.40 जैसा कि ऊपर दिए गए खंडों में बताया गया है, वैश्विक अर्थव्यवस्था अब ऐसे चरण में प्रवेश कर रही है, जहाँ पारंपरिक, मौलिक नीतिगत नियंत्रक जो कभी प्रभावी थे, अब लागू नहीं हो सकते हैं या प्रासंगिक भी नहीं रह सकते हैं। पूरे विश्व में, वैश्विक स्तर पर नीति निर्माण का केंद्र आंतरिक हो गया है। खुले व्यापार, पूंजी और प्रौद्योगिकी का मुक्त प्रवाह और नियमों के प्रति सम्मान के साथ एक वैश्वीकृत विश्व से आपसी लाभों की उम्मीद अब अतीत की बातें हो सकती हैं। यह जितना वास्तविक है उतना ही अप्रिय और दुर्भाग्यपूर्ण भी है।

5.41 स्पष्ट रूप से कहें तो हम यह सुझाव नहीं दे रहें हैं कि भारत स्वयं को विश्व से दूर कर ले। इसके विपरीत, शेष विश्व में मौजूदा प्रवृत्तियों के कारण भारत को निर्यात बढ़ाने और निवेश आकर्षित करने के लिए अपने प्रयासों को दोगुना करना होगा। ऐसा करने का एक तरीका है कि अपने आप को अपने अतीत के बजाय शेष विश्व के साथ बेंचमार्क स्थापित करना है। हालांकि, अनिश्चित वैश्विक वातावरण और भयावह भू-राजनीति को देखते हुए हमारे आर्थिक विकास में बाहरी क्षेत्र के योगदान की अपेक्षाएँ उचित रूप से यथार्थवादी होनी चाहिए। इसलिए, हमें घरेलू मोर्चे पर अपने प्रयासों को और तेज करने की आवश्यकता है।

5.42 जीवन स्तर में निरंतर वृद्धि हासिल करने के लिए, भारतीय अर्थव्यवस्था को कम-से-कम एक दशक तक प्रत्येक वर्ष वास्तविक रूप से लगभग 8% की दर से बढ़ने की आवश्यकता होगी। इस विकास को प्राप्त करने हेतु, निवेश दर को जीडीपी के लगभग 31% के वर्तमान स्तर से बढ़ाकर जीडीपी के

लगभग 35% तक लाना होगा। सामान्य तौर पर, यह वांछनीय है कि निवेश दर में वृद्धि हो ताकि उच्च जीडीपी विकास दर हासिल की जा सके। पूर्वी एशियाई अर्थव्यवस्थाओं का यही अनुभव रहा है, जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जापान से शुरू होकर पिछले चार दशकों में चीन के साथ समाप्त हुआ है।

5.43 जैसा कि पिछले खंडों में विस्तार से बताया गया है, इस संदर्भ में अत्यधिक बदलाव आया है। इसलिए, जैसा कि बाह्य क्षेत्र का विकास संबंधी अध्याय 3 में चर्चा की गई है कि घरेलू बचत को संपूरित करने वाली बाहरी बचत द्वारा समर्थित निवेश की मात्रा का पुनर्मूल्यांकन किया जाना चाहिए। इसका तात्पर्य है कि आर्थिक विकास के लिए निवेश दर बढ़ाने से ज्यादा निवेश संबंधी मामलों की दक्षता बढ़ाना मायने रखता है। निवेश दक्षता दर में वृद्धि निवेश द्वारा उत्पादन सृजन करने में लगने वाले समय को कम करके और निवेश की प्रति इकाई अधिक उत्पादन उत्पन्न करके हासिल किया जाता है।

5.44 निवेश और आर्थिक दक्षता में वृद्धि के माध्यम से भारत में घरेलू नेतृत्व वाली वृद्धि की क्षमता को उन्मुक्त करने के लिए संयोजित प्रयास आवश्यक होगा, जैसे कि विनियमन की वास्तविक/सच्ची लागत का आकलन करना, मानकों और नियंत्रणों को उदार बनाकर इसे कम करने/हटाने के लिए व्यवस्थित विनियमन करना और नागरिकों तथा व्यवसायों के लिए समान रूप से आर्थिक गतिविधिक शुरू करने की लागत और बोझ को कम करने वाली नीति का निर्धारण करना है। भारत को आर्थिक स्वतंत्रता को प्रोत्साहित करने वाली नीतिगत कार्रवाइयों को अपनाने के माध्यम अर्थात् नागरिकों की वैध आर्थिक और उद्यमशीलता संबंधी आकांक्षाओं की निर्बाध क्षमता को प्रोत्साहन देकर आर्थिक विकास को गति देनी चाहिए।

गैर-विनियमन और आर्थिक स्वतंत्रता: विकास के लिए उत्प्रेरक

5.45 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के विकास के लिए गैर-विनियमन बड़े उद्यमों की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण है। समय और वित्तीय संसाधनों के संदर्भ में अनुपालन लागत एमएसएमई के लिए नगण्य नहीं है। बड़े उद्यम सामान्यतौर पर अनुपालन से बचने का कोई न कोई रास्ता खोज लेते हैं। छोटे उद्यमों के लिए प्रबंधन और वित्तीय बैंडविड्थ सीमित है। इसलिए, गैर-विनियमन छोटे व्यवसायों के लिए एक नीतिगत एजेंडा है[36]। पिछले दशक में, भारतीय नीतिगत बल में इस दृष्टिकोण के बारे में जागरूकता का प्रदर्शन किया गया है, जिसमें व्यापक प्रक्रिया और शासन सुधारों के लिए एक ढांचा स्थापित करते समय गैर-विनियमन के महत्व और तात्कालिकता को मान्यता दी गई है। इन सुधारों के पहले चरण में अनुपालन बोझ को कम करने, प्रणालियों, प्रक्रियाओं और सूचनाओं को सुव्यवस्थित तथा डिजिटल बनाने एवं विशिष्ट क्षेत्रों के लिए प्रोत्साहन प्रदान करने पर ध्यान दिया गया है। केंद्र सरकार ने प्रक्रिया और शासन स्तर पर सुधारों को लागू करके, कराधान कानूनों को सरल बनाकर, श्रम नियमों को युक्तिसंगत बनाकर और व्यावसायिक कानूनों को अपराध की श्रेणी से हटाकर गैर-विनियमन किया है। उदाहरण के लिए, केंद्र सरकार ने संसद में वन विनियमों में सुधार लाए जो उद्यमों को उनकी संपत्ति से मुख्य सड़क तक मार्ग बनाने जैसे सरल कार्य करने में बाधा बन रहे थे।

36 वन संरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2023 (2023 की संख्या 15)।

5.46 राज्यों ने भी अपनी ओर से अनुपालन बोझ को कम करके और प्रक्रियाओं को सरल और डिजिटल बनाकर गैर-विनियमन में भाग लिया है। राज्यों ने कष्टकारी बिंदुओं की पहचान करने के लिए व्यवसायों के साथ जुड़कर विनियमन की लागत को कम करने का प्रयास किया है। उदाहरण के लिए, हरियाणा और तमिलनाडु ने निर्माण को आसान बनाने के लिए पिछले दशक में 12 बार अपने भवन विनियमों में संशोधन किए[37]। इसी तरह, पंजाब ने उद्योगों के साथ शिकायत निवारण सत्र आयोजित किए और कई भवन, श्रम और अग्नि विनियमों को उदार बनाया[38]। इसी तरह, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और हरियाणा ने सशर्त छूट की व्यवस्था करके सूचना-प्रौद्योगिकी-सक्षम-सेवा (आईटीईएस) उद्योगों के लिए रात्रि पाली में महिलाओं को काम पर रखने पर प्रतिबंधों में ढील दी है और उत्तर प्रदेश ने होटलों के लिए भवन विनियमों में ढील दी है[39]।

5.47 उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग द्वारा तैयार किए गए व्यापार सुधार कार्य योजना (बीआरएपी) के अनुसार राज्यों का किया गया मूल्यांकन ऊपर की परिकल्पना की पुष्टि करता है और दर्शाता है कि गैर-विनियमन से औद्योगिकीकरण को बढ़ावा मिलता है। इस आर्थिक सर्वेक्षण के उद्योग अध्याय का चार्ट VII.22 राज्यों में व्यापार करने की सुगमता और औद्योगिक गतिविधि के स्तर के बीच सकारात्मक सहसंबंध दर्शाता है, जो महत्वाकांक्षी और उभरते राज्यों में गैर-विनियमन और उद्यम-अनुकूल सुधारों की आवश्यकता का सुझाव देता है। ये निष्कर्ष उन अंतरराष्ट्रीय अनुभवों से मेल खाते हैं जो देशों को गैर विनियमन लागू करते समय मिले हैं जैसे कि उपभोक्ता कल्याण में वृद्धि, उद्योग में प्रतिस्पर्धा और नवाचार को सुविधाजनक बनाना और आर्थिक विकास पर समग्र सकारात्मक प्रभाव (विंस्टन, 1993)[40]।

5.48 ऐसे प्रयासों ने राज्यों के लिए अब सुधारों के अगले दौर की शुरुआत करने की नींव रखी है, जिसकी तत्काल आवश्यकता है तथा जिसकी संभावनाएं भी बहुत अधिक हैं। कई राज्यों ने अगले दो दशकों में बिलियन से ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य रखा है। हालांकि, मौजूदा नियम बाजार में प्रवेश की लागत बढ़ाकर, संचालन के लिए अक्षम मॉडल को जबरन लागू करके और औद्योगिक रूग्णता को दीर्घकालिक बनाकर विकास के लिए बाध्यकारी बाधाओं के रूप में कार्य करते हैं। विनियमन व्यवसायों के समय से शुरू करने और बढ़ने की क्षमता को नुकसान पहुंचाते हैं। उदाहरण के लिए, फैक्ट्री नियम किसी व्यवसाय के लिए 300 कर्मचारियों वाली एक फैक्ट्री[41] चलाने की तुलना में 150 कर्मचारियों वाली दो फैक्ट्रियों को चलाना सस्ता बनाते हैं, जिससे स्केल अर्थव्यवस्था हतोत्साहित होती है। विनियम रोजगार सृजन को हतोत्साहित करके, मजदूरी को सीमित करके और अनौपचारिक रोजगार को प्रोत्साहित करके

37 आनंद, बी.; रॉय, एस. और कौर, एस. (2024, 17 अप्रैल)। 'भवन विनियमों में संशोधन के रुझान'। https://prosperiti. substack. com/p/24-trends-in-amendments-to-building

38 https://www.businesstoday.in/latest/economy/story/sarkar-sanatkar-milni-industrialists-appreciate-punjab-cms-initia- tive-in-jalandhar-398806-2023-09-18

39 हरियाणा में रात्रि में महिलाओं के रोजगार की शर्तें: Conditions for women's employment at night in Haryana: https:// storage.hrylabour.gov.in/uploads/labour_laws/ Y2023/March/W1/D02/1677736151.pdf

कर्नाटक में रात में महिलाओं को काम पर रखने की शर्तें: https://dpal.karnataka.gov.in/storage/pdf-files/Acts%20&%20 Ordi- nance/40%20of%202020%20(E).pdf

उत्तर प्रदेश ने होटलों के लिए भवन नियमों में संशोधन किया: https://invest.up.gov.in/wp-content/uploads/2024/07/UP-amends_070724.pdf

40 विंस्टन, सी. (1993). आर्थिक विनियमन: माइक्रोइकोनॉमिस्ट के लिए गणना के दिन. जर्नल ऑफ इकोनॉमिक लिटरेचर, 31 (3), 1263–1289. http://www.jstor.org/stable/2728241.

41 अध्याय V, कारखाना अधिनियम, 1948 (1948 का संख्या 63)।

श्रमिकों को भी नुकसान पहुंचाते हैं। उदाहरण के लिए, भारतीय श्रमिक औपचारिक रूप से समयोपरि श्रम नहीं कर सकते क्योंकि विधि के अनुसार नियोक्ताओं को नियमित मजदूरी से कम-से-कम दोगुना भुगतान करना आवश्यक है। भारतीय श्रमिक समयोपरि वेतन प्राप्त करने के लिए अनौपचारिक रोजगार स्वीकार करते हैं।

5.49 विनियमों से फर्मों में सभी प्रचालनात्मक निर्णयों की लागत में वृद्धि होती है। उदाहरण के लिए, फैक्ट्री मालिकों को भूमि उपयोग परिवर्तन [सीएलयू] लाइसेंस प्राप्त करने और आंचलिक विनियमनों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए समय और संसाधन समर्पित करने चाहिए। फैक्ट्री मालिकों को परिवहन, अतिरिक्त भूमि, विश्राम कक्षों और कैंटीनों के निर्माण और महिलाओं को रात की पाली में काम पर रखने के लिए कागजी कार्रवाई में भी निवेश करना चाहिए। मौजूदा विनियम नवाचार और सृजनात्मक तोड़-फोड़ को भी हतोत्साहित करते हैं। इसी तरह, प्रशिक्षुओं पर काम के घंटे की सीमा के कारण भारतीय औपचारिक शिक्षा प्राप्त करते समय प्रशिक्षुता नहीं कर सकते हैं।

5.50 अनेक मामलों में, मौजूदा नियमन बहुत मूल्यवान हैं, अर्थात् वे विनियामक क्षमता और विनियमित संस्थाओं की अनुपालन क्षमता की संवर्धित धारणा के साथ निर्धारित किए गए हैं। कई मौजूदा विनियमों को अंतरराष्ट्रीय निकायों द्वारा अनुशंसित और अन्य देशों द्वारा अपनाए गए तुलनीय मानकों के अनुसार कम प्रतिबंधात्मक किए जाने की कुछ गुंजाइश है।

5.51 उनकी आर्थिक क्षमता को ध्यान में रखते हुए, भारतीय फर्में विकास के अवसरों को खतरे में डाले बिना, निवेश तथा रोजगार सृजन को नुकसान पहुंचाए बिना लागू विनियमनों का अनुपालन नहीं कर सकती हैं। उदाहरण के लिए, यदि वर्ष के विशिष्ट मासों के दौरान मांग में वृद्धि होती है, तो निर्यात करने वाली फर्मों के पास अधिक श्रम घंटे बढ़ाने और अव्यस्त काल में उन्हें श्रम घंटों को कम करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। यह स्वतंत्रता अपेक्षित है। भारतीय विनियमन नियोक्ताओं को अनुपालन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संभावित वृद्धि और रोजगार के अवसरों से संसाधनों को हटाने के लिए मजबूर करते हैं। उदाहरण के लिए, 5,000 वर्ग मीटर के प्लॉट वाले भारतीय फैक्ट्री मालिकों को निर्माण मानकों का पालन करने के लिए अपने प्लॉट का 69 प्रतिशत तक हिस्सा छोड़ना पड़ सकता है। ऐसी भूमि के इस हिस्से की कीमत ₹1.58 करोड़ तक हो सकती है और इसका इस्तेमाल 509 अतिरिक्त नौकरियों के सृजन के लिए किया जा सकता था[42]।

5.52 संक्षेप में, भारत को जिस तीव्र आर्थिक विकास की आवश्यकता है, वह तभी संभव हो पाएगी जब संघ और राज्य सरकारें ऐसे सुधारों को लागू करना जारी रखें जिनसे लघु तथा मध्यम उद्यमों को कुशलतापूर्वक संचालन और लागत-प्रभावी प्रतिस्पर्धा करने की अनुमति मिल सके। विनियम युक्तिसंगत बनाया जाना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि विनियम अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए न्यूनतम आवश्यक हो और लघु तथा मध्यम उद्यमों के पास सीमित प्रबंधकीय तथा अन्य संसाधनों को ध्यान में रखते हुए अधिकतम व्यवहार्य हो। सुधारों और आर्थिक नीति का ध्यान अब सुव्यवस्थित अविनियम पर होना चाहिए।

42 https://prosperiti.org.in/wp-content/uploads/2024/01/State-of-Regulation-Report_Building-Standards_December-2023.pdf

5.53 राज्य तीन-चरणीय प्रक्रिया का पालन करके लागत-प्रभावशीलता के लिए विनियमनों की सुव्यवस्थित समीक्षा करके सुव्यवस्थित रूप से अविनियमन कर सकते हैं:

- **गैरविनियमन हेतु क्षेत्रों की पहचान:** ईओडीबी 2.0 राज्य सरकार के नेतृत्व वाली एक ऐसी पहल होनी चाहिए, जो कारोबार करने में होने वाली असुविधा के मूल कारणों में सुधार करने पर केंद्रित हो। राज्य केवल कार्यान्वयन एजेंसियां नहीं हैं अपितु नियम बनाने वाले निकाय हैं। राज्यों के पास सूची II के विषयों जैसे भूमि, भवन, जल और स्थानीय व्यापार तथा वाणिज्य को विनियमित करने का विशेष क्षेत्राधिकार है। राज्य सूची III के विषयों जैसे श्रम कल्याण, विद्युत और यांत्रिक संसाधनों[43] पर संघ सरकार के साथ विनियमन भी कर सकते हैं। राज्य प्राथमिक विधि में संशोधन करके इन सभी विषयों पर विधियों का व्यवस्थित रूप से अविनियमन कर सकते हैं। जहां संघ सरकार प्राथमिक विधि निर्धारित करती है, वहीं दूसरी ओर राज्यों के पास अधीनस्थ विनियमों में संशोधन करके अविनियमन करने का विकल्प भी होता है। अविनियमन करने के अवसरों की पहचान करते समय राज्यों द्वारा इन विकल्पों पर विचार करना चाहिए। राज्य सुधार के अवसरों का पता लगाने के लिए विनियमन के निम्नलिखित क्षेत्रों [तालिका V.1 देखें] पर विचार कर सकते हैं:

तालिका V.1: व्यवसायों को प्रभावित करने वाले विनियमन क्षेत्रों और प्रावधानों की सूची

क्षेत्र	विनियमनों के उदाहरण
विधिक स्थिति और प्रशासन	नगरपालिका संबंधी विधि, नागरिक चार्टर, सार्वजनिक सेवा संवितरण में जवाबदेही
भूमि	भू-राजस्व, भूमि सुधार, नगर एवं राष्ट्र योजना बनाना, भूमि सीमा
भवन एवं निर्माण	नगर एवं राष्ट्र योजना बनाना, भवन उपनियम, अग्नि संरक्षा विधि
श्रम	संघ संहिताओं, फैक्ट्रियों, संविदा श्रमिक, दुकानों के विधि के अंतर्गत नियम
जन-उपयोगी सेवाएं	जल, विद्युत, भवन संबंधी उपविधियां, नगरपालिका संबंधी विधि
परिवहन	मोटर वाहन विधियां, मोटर परिवहन श्रमिक विधियां, माल की ढुलाई
लॉजिसटिक्स	वेयरहाउसिंग और लॉजिसटिक्स नीतियां, भवन संबंधी उपनियम
क्रय और विक्रय	कृषि उपज एवं पशुधन बाजार समिति कानून
पर्यावरण जल	वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण के लिए विधिया
क्षेत्र विशेष	उत्पाद शुल्क, खाद्य सुरक्षा, विधिक माप विज्ञान

विनियमन के इन प्रत्येक क्षेत्रों में, राज्य अधिदेश जारी करता है जिनमें परमिट, मानक, मूल्य और मात्रा नियंत्रण, शुल्क और कर, अनुपालन, निरीक्षण और शास्ति शामिल हैं। प्रत्येक मूल अधिदेश व्यवसाय शुरू करने और उसके संचालन की लागत, समय और अनिश्चितता को बढ़ाता है, जिससे गहन आर्थिक गतिविधि और उद्यमों की वृद्धि हतोत्साहित होती है। मानकों और नियंत्रणों को उदार बनाना, लाइसेंसिंग मानदंडों को संशोधित करना, विनियामक सीमाओं को संशोधित करना, उद्यम विकास में बाधाओं को कम करना और प्रक्रियात्मक रक्षोपाय को लागू करने जैसे कुछ सुधार संबंधी उदाहरण हैं, जिनमें कार्रवाई अपेक्षित है। इसके पश्चात, राज्यों द्वारा निर्णय लेने में अधिक स्वतंत्रता की अनुमति देने के लिए विनियमनों में पंक्ति-दर-पंक्ति सुधार लागू किए जाने चाहिए।

43 सातवीं अनुसूची, भारतीय संविधान, 1950

- **अन्य राज्यों और राष्ट्रों के साथ विनियमों की विचारपूर्वक तुलना करना:** राज्यों को विकास को प्रेरित करने वाले सुधारों के अवसरों की पहचान करने के लिए विनियमों की अंतर-राज्यीय और अंतर-देशीय तुलना से सीख लेनी चाहिए। राज्य एक-दूसरे के नवीन अविनियमन अनुभवों और आम समस्याओं के प्रति लागू रचनात्मक समाधानों से सीख सकते हैं। अविनियमन करने वाले अन्य राज्यों के उदाहरण से सीखने से अन्वेषण में लगने वाले समय की बचत हो सकती है। उदाहरण के लिए, सन 2000 के दशक के आरंभ तक सभी राज्यों ने महिलाओं को रात की पाली में काम करने से प्रतिबंधित कर दिया था। पिछले कुछ वर्षों में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और हरियाणा जैसे राज्यों ने पहले अनुमति-आधारित प्रणाली और फिर परिस्थिति आधारित-प्रणाली[44] में अंतरित होकर महिला संबंधी भागीदारी के अवसरों को अविनियमित करना प्रारंभ किया। कुछ राज्यों ने आईटी उद्योग में महिलाओं की भागीदारी को पूरी तरह से अविनियमित कर दिया है। ऐसी पहलें और अनुभव सभी राज्यों द्वारा सीख प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण हैं।

  इसके अलावा, विनियम के साथ अंतर्राष्ट्रीय अनुभव भी कुछ महत्वपूर्ण सबक देते हैं। कई मुद्दों पर, अन्य देश (और अन्य देशों के राज्य) अधिक नियंत्रणकारी स्थिति से अधिक अविनियमित स्थिति में परिवर्तित हो गए हैं। केवल पड़ोसी एशियाई देशों में, नागरिक कल्याण को खतरे में डाले बिना कम कठोर विनियम लागू किए जाने के कई संदर्भ-उपयुक्त उदाहरण हैं। उदाहरण के लिए, जापान घनी आबादी वाले शहरी क्षेत्रों में मिश्रित उपयोग वाले विकास की अनुमति देता है, और कोरिया साप्ताहिक कार्य घंटे की सीमा को 6 महीने[45] से अधिक औसत करने की अनुमति देता है। दूर, और भी अधिक उपयोगी सबक हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, संयुक्त राज्य अमेरिका के कुछ हिस्सों ने ''विकास को अधिकार रखने'' का रुख अपनाया है, जिससे निर्माण पूर्व अनुमोदन चरणों[46] की संख्या कम हो गई है। भारत में प्रतिस्पर्धी संघवाद का उदय राज्यों को निवेश आकर्षित करने के लिए नियामक बोझ को सरल बनाने और कम करने में इस तरह के अंतर्राष्ट्रीय अनुभवों को लागू करने की अनुमति देता है। हालाँकि, जिन पद्धतियों को सर्वोत्तम प्रथाओं के रूप में देखा जा सकता है, उनका अनुकरण करने में कुछ सावधानी बरतनी चाहिए। केवल 'सर्वोत्तम पद्धतियों' की खोज करने के बजाय, राज्यों को विनियमन के लिए न्यूनतम आवश्यक, अधिकतम व्यवहार्य विकल्प की पहचान करनी चाहिए।

- **व्यक्तिगत उद्यमों पर इन विनियमों में से प्रत्येक की लागत का अनुमान लगाना:** प्रत्येक विनियम मौद्रिक, अवसर और राज्य क्षमता लागत लगाता है। अधिकांश विनियमों में अनुपालन सुनिश्चित करने और प्रदर्शित करने के लिए व्यवसायों को कुछ पैसा खर्च करने की आवश्यकता होती है। इस मौद्रिक लागत को अक्सर पूर्ववत उद्यमशील अवसरों के साथ जोड़ा जाता है। इसके अलावा, प्रत्येक जनादेश में अनुपालन की जांच और उसे लागू करने की क्षमता की आवश्यकता होती है। राज्यों को पारित होने से पहले प्रत्येक विनियमन के इकाई-स्तरीय प्रभाव के लिए व्यवस्थित रूप से उत्तरदायी होना चाहिए। उदाहरण के लिए, भारतीय राज्यों को सैटबैक के लिए

---

44 कर्नाटक: कर्नाटक दुकानें और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान (संशोधन) अधिनियम, 2002 (2002 की संख्या 14)
हरियाणा: अधिसूचना संख्या 6/35/2002-1Lab
आंध्र प्रदेश: जीओएम संख्या 16, एलईटी एंड एफ (लैब II) विभाग, दिनांक: 30.05.2002।

45 जापान: नगर नियोजन अधिनियम, अधिनियम सं. 100.
दक्षिण कोरिया: श्रम मानक अधिनियम, अधिनियम सं. 11270.

46 संयुक्त राज्य अमेरिका: मैसाचुसेट्स सामान्य कानून सी. 40ए

> 1,164 से 3,522 वर्ग मीटर तक भूमि छोड़ने के लिए 10,000 वर्ग मीटर भूखंड वाले कारखानों की आवश्यकता होती है। इसके परिणामस्वरूप, सैटबैक विनियमों से भारतीय कारखानों को 97.50 लाख तक मूल्य की भूमि का उत्पादक मूल्य और 521 नौकरियों[47] का सृजन करने का अवसर मिला। यह बहस का विषय नहीं है कि सैटबैक विनियम को समाप्त किया जाए किन्तु इसके तर्क में ये विनियम ऐसे होने चाहिए जिसमें (डैडवेट लॉस) आर्थिक उत्पादक्ता हानि और प्रत्येक ऐसे अधिकरोपण की अवसर लागत को गंभीरता से लिया जाए।

राज्यों को विनियमों के अनपेक्षित परिणामों का भी अनुमान लगाना चाहिए। राज्य अक्सर बिना यह जाने कि विनियम दीर्घकालिक रूप से व्यवसायों को कैसे प्रभावित कर सकते हैं, कुछ कल्याणकारी उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए नियम निर्धारित करते हैं, उदाहरण के लिए, कई राज्य सार्वजनिक सड़कों के किनारे की भूमि की पट्टियों को 'संरक्षित वन' के रूप में वर्गीकृत करते हैं। राज्यों ने आबादी वाले क्षेत्रों में वृक्ष आच्छादन के लिए सुरक्षा बढ़ाने के लिए स्वतंत्रता के बाद पहले दो दशकों में इन 'पट्टी वनों' को वर्गीकृत किया। वर्षों से, इस सरल वर्गीकरण के परिणामस्वरूप व्यवसायों को सरल मार्ग अभिगम अनुमोदन के लिए अनुमोदन प्राप्त करने में 250 दिनों से अधिक का समय लगा है। ये लागतें आबादी वाले क्षेत्रों में वृक्ष आवरण की रक्षा के लाभ के लिए असमान हैं और पूरी तरह से अनपेक्षित थीं। इस तरह के मानक उन बाध्यकारी बाधा जिसके तहत भारतीय राज्य काम करते है ---- जो अभी भी राज्य की विकसित हो रही क्षमता है, को देखते हुए अवास्तविक अपेक्षाएं स्थापित करती है। अक्सर, ये मानक उच्च-राज्य क्षमता वाले देशों में निर्धारित मानकों की नकल करते हैं, जिनमें अनुरूप कार्यात्मकता नहीं होती है। उदाहरण के लिए, आज 3,21,578 कारखानों[48] में अनुपालन की देखरेख के लिए केवल 644 कार्यरत निरीक्षक उपलब्ध हैं, जिनमें से प्रत्येक लगभग 500 कारखानों की देखरेख करता है। कम राज्य क्षमता वाली प्रशासनिक प्रणालियों के तहत, अवास्तविक अपेक्षाओं से ''समय से पहले भार वहन''[49] हो सकती है। भविष्य में, राज्य प्रत्येक विनियमन के लिए सुधार विकल्पों को तैयार करने के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में दृष्टिकोण की निम्नलिखित सूची पर विचार कर सकते हैं [तालिका V.2 देखें]:

47 आनंद, बी रॉय, एस कौर, एस. (2024)। 'स्टेट आफ रेगुलेशन: बिल्डिंग स्टैन्डर्डस रीफॉर्मसफॉर जॉब्स एण्ड ग्रोथ'।

48 डीजीएफएएसएलआई (2022)। 'मानक संदर्भ नोट'।

49 एंड्रयूज, मैट; प्रिटचेट, लैंट; वूलॉक, माइकल। (जनवरी, 2017)। 'प्रीमेच्योर लोड बेयरिंग: डुईंग टू मच टू सून'। बिल्डिंग स्टेट कैपबिलिटी: एविडेंस, एनालिसिस, एक्शन (ऑक्सफोर्ड, 2017; ऑनलाइन इडिएन, ऑक्सफोर्ड अकादमिक, 16 फरवरी 2017),https://doi.org/10.1093/acprof% oso/9780198747482.003.0004

तालिका V.2: व्यवसायों को प्रभावित करने वाले कानूनों में सुधार के लिए संभावित दृष्टिकोण की सूची

सुधार के प्रति दृष्टिकोण	वर्णन	स्थिति
अनुपालन के बोझ को कम करना	कानूनों का पालन करने के लिए व्यवसायों द्वारा की जाने वाली प्रशासनिक लागतों को कम करना।	ईओडीबी के प्रथम चरण में पहले ही लागू कर लिया गया है।
प्रणालियों, प्रक्रियाओं ओर सूचना को सुव्यवस्थित करना	अनावश्यकताओं को दूर करने, प्रक्रिया प्रवाह को सरल बनाने तथा सरकारी सेवाओं की पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए व्यवसाय-सरकार के बीच बातचीत की प्रक्रियाओं को संशोधित करना।	
प्रणाली, प्रक्रियाओं और सूचना का डिजिटलीकरण	दक्षता में सुधार के लिए व्यवसायों के साथ बातचीत करने के लिए डिजिटल साधन स्थापित करें।	
प्रोत्साहन उपलब्ध कराना	प्रमुख क्षेत्रों या व्यवसायों के समूहों को विशेष लाभ दें।	
प्रवर्तन के लिए विधिक	बाजारों को विकृत करने वाले नियंत्रण ाों को कम करें, नियमों को निर्धारित करने के लिए 'न्यूनतम' न्यूनतम आवश्यक, अधिकतम व्यवहार्य 'व्यवहार्य' दृष्टिकोण अपनाएं	इसे ईओडीबी के चारण– 2 में लागू किया जाएगा।
रक्षोपाय निर्धारित करना	विवादों के तथ्य– आधारित समाधान को प्रोत्साहित करने के लिए उचित प्रक्रिया मानदंडों का पालन सुनिश्चित करना।	
प्रशुल्क और शुल्क में कमी	उपयोगिता लागतों को बढ़ाने वाले अनिवार्य शुल्कों को कम करना या हटाना।	
जोखिम आधारित विनियम का प्रयोग	व्यवसायों के जोखिम प्रोफाइल के अनुरूप कानूनी मानदंड बनाना, प्रवर्तन में तीसरे पक्ष को शामिल करना।	

5.54 राज्यों ने ईओडीबी सुधारों के पहले चरण में इन आठ में से चार दृष्टिकोण अपनाए हैं, अगले चरण में, उन्हें मानकों और नियंत्रणों को उदार बनाने, प्रवर्तन के लिए कानूनी सुरक्षा उपाय स्थापित करने, प्रशुल्क और शुल्क को कम करने और जोखिम-आधारित विनियमन को लागू करने पर नई पहल करनी चाहिए।

- **मानकों और नियंत्रणों को उदार बनाना:** राज्य भारतीय व्यवसायों पर मानकों और नियंत्रणों को उदार बनाकर अनुपालन की लागत को कम कर सकते हैं। भारतीय नियमों के अनुसार फर्मों

को समय और धन का निवेश करना चाहिए और अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए विकास के अवसरों को छोड़ना चाहिए। इन विनियमों की जांच यह सुनिश्चित करने के लिए की जानी चाहिए कि वे अपने सामाजिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक सबसे कम लागत लगाते हैं। इस संबंध में विशिष्ट उदाहरण बॉक्स V.1 में उल्लिखित किए गए हैं।

- **शास्ति और प्रवर्तन के लिए विधिक रक्षोपाय निर्धारित करना:** राज्य नागरिक शास्तियां और लाइसेंस रद्द करने जैसी दंडात्मक कार्रवाइयों के माध्यम से कई विनियमों को लागू कर सकते है। ये दंडात्मक कार्यवाइयां व्यवसायों की कानूनी सीमाओं के भीतर संचालन की क्षमता को सीमित कर सकती हैं। राज्य इस तरह की दंडात्मक कार्रवाई की सटीकता और पारदर्शिता बढ़ाकर निवेश के माहौल में सुधार कर सकते हैं। बॉक्स V.1 में विशिष्ट उदाहरण देखें।

- **प्रशुल्क और शुल्क को कम करना:** राज्य प्रशुल्क और करों को लागू करके भारतीय व्यवसायों के संचालन और विकास पर प्रत्यक्ष लागत लगाते हैं। जबकि ये नियम सार्वजनिक खर्च का समर्थन करते हैं, ये नियम भारतीय व्यवसायों की प्रतिस्पर्धात्मकता को भी कम कर सकते हैं। राज्य अन्य क्षेत्राधिकारों, उप-राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप प्रशुल्क और शुल्क को तर्कसंगत बनाकर निरंतर विकास को प्रोत्साहित कर सकते हैं। बॉक्स V.1 में विशिष्ट उदाहरण देखें।

- **जोखिम-आधारित विनियमन लागू करना:** राज्य उन व्यवसायों पर समान नियम लागू करते हैं जो कुछ सामाजिक रूप से अवांछनीय परिणामों जैसे आग, प्रदूषण और भवन ढहने के अलग-अलग जोखिम पैदा करते हैं। इसके परिणामस्वरूप अक्सर कम और मध्यम जोखिम वाले व्यवसायों को अनुपालन की अत्यधिक उच्च लागत का सामना करना पड़ता है। इस तरह के सामान्य विनियमों के तहत, राज्य के विभाग भी जोखिम वाले व्यवसायों की जांच करने के लिए संघर्ष करते हैं। जोखिम-आधारित विनियमन को अपनाकर, राज्य विभाग अग्नि सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण जैसे सामाजिक लाभ उत्पन्न करने के लिए सार्वजनिक संसाधनों को ईष्टतम कर सकते हैं। जोखिम-आधारित विनियमों के तहत, कम और मध्यम जोखिम वाले व्यवसायों को प्रर्याप्त सार्वजनिक सुरक्षा और स्वास्थ्य संबंधी कटौती के बिना कम अनुपालन लागत का सामना करना पड़ेगा।

बॉक्स V.2: ईओडीबी 2.0 के पक्ष में तर्क देना

क. मानकों और नियंत्रणों का उदारीकरण

कारखाना संबंधी प्रक्रियाओं में महिलाओं के काम करने पर प्रतिबंध हटाना: भारतीय राज्य महिलाओं को कई कारखाना प्रक्रियाओं से प्रतिबंधित करते हैं। भारत के दस सबसे अधिक आबादी वाले राज्य सामूहिक रूप से महिलाओं को विशिष्ट कारखाना प्रक्रियाओं में भाग लेने पर 139 प्रतिबंध लगाते हैं। सरकारें प्रक्रियाओं की खतरनाक प्रकृति को देखते हुए इन प्रतिबंधों को लागू करती हैं। हालांकि, अंतर-राज्यीय तुलना और वैज्ञानिक साहित्य से संकेत मिलता है कि इन प्रतिबंधों को महिला श्रमिकों के लिए विशेष स्वास्थ्य जोखिमों के सबूत के बिना लागू किया जाता है।

उदाहरण के लिए, कुछ राज्य महिलाओं को अपघर्षक विस्फोट (धातु की सतहों को साफ करने के लिए उपयोग किया जाता है) में भाग लेने की अनुमति देते हैं, लेकिन अन्य राज्य महिलाओं को उसी प्रक्रिया में भाग लेने से रोकते हैं। इसी तरह, महिलाओं पर सीसा या उसके यौगिकों के निर्माण की

किसी भी प्रक्रिया में भाग लेने से मना किया जाता है। हालांकि, वैज्ञानिक साहित्य इंगित करता है कि सीसा से महिलाओं के लिए विशेष स्वास्थ्य जोखिम पैदा होने की संभावना नहीं है। ये प्रतिबंध महिलाओं को उच्च वेतन वाली नौकरियों से बाहर रखते हैं, जिससे प्रतिबंध उत्पादन प्रतिकूल हो जाते हैं।

औद्योगिक और वाणिज्यिक भूखंडों में भूमि के नुकसान को कम करने के लिए पार्किंग मानदंडों को तर्कसंगत बनाना: कई भारतीय राज्यों में वाणिज्यिक भवनों को कुछ सीमावर्ती राज्यों और देशों के समान तल स्थान प्राप्त करने के लिए अधिक मंजिलों का निर्माण करना चाहिए। यह भारतीय वाणिज्यिक भवनों को कृत्रिम रूप से पतला बनाता है, मूल्यवान वाणिज्यिक भूमि को बर्बाद करता है और निर्माण की लागत को बढ़ाता है। ऐसी प्रतिबंधात्मक सैटबैक और जमीनी कवरेज विनियमों के कारण होता है जो वाणिज्यिक भवनों को अन्य देशों की तुलना में अधिक पतला अनुपात रखने के लिए मजबूर करते हैं। इसलिए, यदि भूतल उपलब्ध हो तो एक ही निर्मित क्षेत्र के लिए एक उद्यमी को अधिक मंजिलों का निर्माण करना चाहिए, जिससे निर्माण लागत अधिक होगी। कई राज्य सरकारों ने 'पर्यटन और आतिथ्य' और सूचना प्रौद्योगिकी को प्रमुख क्षेत्रों के रूप में नामोदिष्ट किया है। राज्यों को इन उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए होटलों और कार्यालयों द्वारा उपयोग की जाने वाली वाणिज्यिक भूमि की उत्पादकता बढ़ानी चाहिए।

ख. शास्तियों और प्रवर्तन के लिए विधिक रक्षोपायनिर्धारित करना

मनमाने प्रशासनिक कार्रवाई की संभावनाओं को कम करने के लिए रक्षोपयों को शामिल करना:

राज्य उचित उपयोग सुनिश्चित करने वाले मानकों से बंधे बिना अनुपालनों को लागू करते हैं प्रशासनिक कानून के मानदंडों के अनुसार, राज्यों को यह सुनिश्चित करने के बाद ही दंडात्मक उपाय करने चाहिए कि आरोपी व्यक्ति को:

1. कथित उल्लंघन के बारे में पर्याप्त तथ्यों के साथ कारण बताओ नोटिस जारी किया गया,
2. तर्क के अपने पक्ष का प्रतिनिधित्व करने का अवसर दिया गया,
3. राज्यों द्वारा अंतिम निर्णय के कारणों का विवरण देते हुए एक तर्कपूर्ण आदेश जारी किया गया, और
4. निर्णयों के विरुद्ध अपील की अनुमति दी गई।

हालांकि, भारतीय नियमों में राज्यों को दंडात्मक कार्रवाई करते समय इन प्रक्रियात्मक रक्षोंपायों उपायों का पालन करने की आवश्यकता नहीं है। उदाहरण के लिए, कई राज्यों में इमारतों को सील करने या ध्वस्त करने से पहले विभागों को विस्तृत कारण बताओ नोटिस जारी करने, आरोपी व्यक्ति द्वारा अभ्यावेदन की अनुमति देने या तर्कपूर्ण निर्णय जारी करने की आवश्यकता नहीं होती है। इन रक्षोंपायों के बिना, राज्यों द्वारा भारतीय शहरों में इमारतों के उपयोग के बारे में त्रुटिपूर्ण या बदनीयती वाले निर्णय लेने की अधिक संभावना है। कानून द्वारा प्रक्रियात्मक सुरक्षा की गारंटी देने से निवेश और रोजगार सृजन के कानूनी जोखिम को कम किया जा सकता है, जिससे त्वरित से विकास को बढ़ावा मिल सकता है।

ग. प्रशुल्कों और शुल्कों को कम करना

औद्योगिक प्रयोक्ताओं के लिए बिजली प्रशुल्क मार्कअप को कम करना: राज्य उद्योगों को बिजली की बिक्री पर उच्च मार्कअप लगाते हैं। यह उच्च मार्कअप उद्योगों को समय के साथ औपचारिक रूप से काम करने और बढ़ने से हतोत्साहित करता है। राज्यों में, औद्योगिक प्रयोक्ता बिजली आपूर्ति के लिए आपूर्ति की लागत पर 10-25% मार्कअप का भुगतान कर सकते हैं। अन्य देश बिजली के उपयोग के लिए कम दरें लगाते हैं। उदाहरण के लिए, वियतनाम बिजली उत्पादन की लागत की तुलना

में 10 प्रतिशत कम दर पर बिजली बिक्री मूल्य निर्धारित करता है। ऊर्जा लागतों में इस तरह के अंतर भारतीय कारखानों की वैश्विक प्रतिस्पर्धा को कम करते हैं, जिससे विकास हतोत्साहित होता है।

घ. जोखिम-आधारित विनियमन लागू करना:

भवन अनुमोदन और निरीक्षण में निजी पक्षों की भूमिका बढ़ाना: भारतीय राज्य निजी पक्षों को भवन सुरक्षा के लिए प्रवर्तन प्रक्रियाओं में भाग लेने के सीमित अवसर देते हैं

यह भारतीय राज्यों की विनियमनों को लागू करने और अनुपालन को बढ़ावा देने की क्षमता को सीमित करता है। भारतीय राज्य निजी पक्षों को केवल प्रारंभिक भवन योजना के अनुमोदन में भाग लेने की अनुमति देते हैं। हालाँकि, बाद के सभी अनुमोदन और निरीक्षण सरकारी अधिकारियों द्वारा किए जाते हैं। अधिकारियों की कमी को देखते हुए, राज्य विभाग निजी पक्षों के साथ राज्य की क्षमता को बढ़ाए बिना बढ़ते शहरों में भवन विनिर्माण संबंधी विनियमनों को लागू नहीं कर सकते हैं।

अन्य देशों में भवन सुरक्षा के लिए प्रवर्तन प्रक्रियाओं में थर्ड पार्टी को शामिल करने के सकारात्मक अनुभव रहे हैं। उदाहरण के लिए, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा ने भवन सुरक्षा विनियमनों के प्रवर्तन को सुनिश्चित करने के लिए सार्वजनिक 'निजी भागीदारी' (पीपीपी) मॉडल को अपनाया। सेवा प्रदायगी की गति, उपलब्धता और विशेषज्ञता के कारण लगभग सत्तर प्रतिशत आवेदकों ने निजी पक्षों से लाइसेंस प्राप्त करने का विकल्प चुना। इस पीपीपी मॉडल ने सार्वजनिक और निजी एजेंसियों के बीच प्रतिस्पर्धा को भी बढ़ावा दिया, जिससे बेहतर प्रवर्तन और सुरक्षा परिणामों को बढ़ावा मिला।

निम्न और मध्यम जोखिम वाली इमारतों के लिए फायर एनओसी की वैधता बढ़ाना: राज्य फायर एनओसी के लिए अल्प वैधता अवधि निर्धारित करते हैं। अल्प वैधता अवधि आवेदकों को एनओसी प्राप्त करने से हतोत्साहित करती है। अधिकांश राज्यों में, उद्योगों को केवल एक से तीन वर्ष के लिए फायर एनओसी जारी की जाती है। एनओसी को नवीनीकृत करने के लिए उद्योग मालिकों को बार-बार इसी तरह की जानकारी देनी होगी। कई राज्यों में आवेदकों को प्रत्येक दो वर्षों में फायर एनओसी प्राप्त करने के लिए इमारत और भू-खंड की संरचना और स्थापना संबंधी बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर देने पड़ते हैं। यद्यपि आवेदक एनओसी के लिए आवेदन करते हैं, किन्तु कुछ राज्य विभागों के पास सभी आवेदनों पर निर्णय लेने के लिए पर्याप्त प्रशासनिक शक्ति नहीं होती है। वैधता अवधि बढ़ाकर, राज्य विभाग अपने प्रशासनिक भार को कम कर सकते हैं और अग्नि सुरक्षा के बिना आवेदकों के लिए अनुपालन लागत को कम कर सकते हैं।

अन्य देशों में भवन सुरक्षा के लिए प्रवर्तन प्रक्रियाओं में थर्ड पार्टी को शामिल करने के सकारात्मक अनुभव रहे हैं। उदाहरण के लिए, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा ने भवन सुरक्षा विनियमनों के प्रवर्तन को सुनिश्चित करने के लिए सार्वजनिक 'निजी भागीदारी' (पीपीपी) मॉडल को अपनाया। सेवा प्रदायगी की गति, उपलब्धता और विशेषज्ञता के कारण लगभग सत्तर प्रतिशत आवेदकों ने निजी पक्षों से लाइसेंस प्राप्त करने का विकल्प चुना। इस पीपीपी मॉडल ने सार्वजनिक और निजी एजेंसियों के बीच प्रतिस्पर्धा को भी बढ़ावा दिया, जिससे बेहतर प्रवर्तन और सुरक्षा परिणामों को बढ़ावा मिला।

निम्न और मध्यम जोखिम वाली इमारतों के लिए फायर एनओसी की वैधता बढ़ाना: राज्य फायर एनओसी के लिए अल्प वैधता अवधि निर्धारित करते हैं। अल्प वैधता अवधि आवेदकों को एनओसी प्राप्त करने से हतोत्साहित करती है। अधिकांश राज्यों में, उद्योगों को केवल एक से तीन वर्ष के लिए फायर एनओसी जारी की जाती है। एनओसी को नवीनीकृत करने के लिए उद्योग मालिकों को बार-बार इसी तरह की जानकारी देनी होगी। कई राज्यों में आवेदकों को प्रत्येक दो वर्षों में फायर एनओसी प्राप्त करने के लिए

इमारत और भू-खंड की संरचना और स्थापना संबंधी बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर देने पड़ते हैं। यद्यपि आवेदक एनओसी के लिए आवेदन करते हैं, किन्तु कुछ राज्य विभागों के पास सभी आवेदनों पर निर्णय लेने के लिए पर्याप्त प्रशासनिक शक्ति नहीं होती है। वैधता अवधि बढ़ाकर, राज्य विभाग अपने प्रशासनिक भार को कम कर सकते हैं और अग्नि सुरक्षा के बिना आवेदकों के लिए अनुपालन लागत को कम कर सकते हैं।

मध्यावधि वृद्धि के लिए नवीनीकृत प्रतिमान

5.55 केंद्र के प्रयासों के पूरक के रूप में, राज्यों को नीतिगत प्राथमिकता के रूप में व्यवस्थित गैर विनियमन को आगे बढ़ाना चाहिए ताकि उत्पादन के कारकों की आर्थिक स्वतंत्रता को बढ़ाया जा सके। फैक्टर मार्किट विनियमन अर्थात् भूमि, श्रम और भवन के उपयोग को प्रभावित करने वाले कानून इसे प्रारंभ करने के लिए सही बिंदु हैं, क्योंकि ये विनियमन सभी उद्यमों में निर्णय लेने की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। राज्य उद्यमों में निर्णय लेने को प्रभावित करने वाले विनियमनों की पहचान करके गैर विनियमन प्रक्रिया आरंभ कर सकते हैं। इसके बाद, राज्य इन मुद्दों के संबंध में अपने विनियमनों की तुलना अन्य राज्यों और देशों के विनियमनों से कर सकते हैं। अंत में, विकल्पों की पहचान करने के बाद, राज्यों को एकल प्रतिरूप उद्यम पर अपने मौजूदा विनियमन के आर्थिक प्रभाव की जांच करनी चाहिए। राज्यों को सभी आर्थिक प्रभावों का संयुक्त विश्लेषण करने की आवश्यकता नहीं है। इसके स्थान पर, राज्य को यह पता लगाने के लिए कि एक उद्यम को अनुपालन के लिए कितने संसाधन, समय की आवश्यकता होगी और इसमें कितना जोखिम की है, डेटा आधारित जानकारी का प्रयोग करना चाहिए।

5.56 आज की तेजी से विकसित हो रही वैश्विक अर्थव्यवस्था में, गैर विनियमन के माध्यम से आर्थिक स्वतंत्रता को बढ़ाने की मांग बढ़ रही है। अति-विनियमन नवाचार और आर्थिक गतिशीलता को बाधित करता है। कई उदाहरणों में, विनियमन, जो उपभोक्ताओं, श्रमिकों और पर्यावरण की रक्षा करने के लिए बनाए गए हैं, वे अनजाने में व्यवसायों के प्रवेश में बाधाएं पैदा कर सकते हैं, प्रतिस्पर्धा को कम कर सकते हैं और नवाचार की गति को धीमा कर सकते हैं। अत्यधिक विनियामक बोझ को कम करके, सरकारें व्यवसायों को अधिक कुशल बनने, लागत कम करने और विकास के नए अवसरों को सृजन में मदद कर सकती हैं। कार्यनीतिक और व्यवस्थित विनियमन विकास, नवाचार और प्रतिस्पर्धात्मकता के लिए उत्प्रेरित कर सकता है।

5.57 नवाचार को बढ़ावा देने और एक व्यवहार्य मिटेलस्टैंड, अर्थात् भारत का एसएमई क्षेत्र सृजित करने के लिए, अवसंरचना और पहलों में निवेश के समान ही व्यवस्थित गैर विनियमन भी महत्वपूर्ण है। जर्मनी, स्विटजरलैंड, जापान और सिंगापुर जैसे देशों की आर्थिक सफलता में मिटेलस्टैंड पर विशेष ध्यान दिए जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इन देशों ने नवाचार को बढ़ावा देने, उच्च गुणवत्ता वाले विनिर्माण को बढ़ावा देने और सुदृढ़ निर्यात अर्थव्यवस्था बनाने के लिए अपने मिटेलस्टैंड की मजबूती का लाभ उठाया है। गैर विनियमन के साथ, भारत का मिटेलस्टैंड राज्यों को आर्थिक नुकसानों से निपटने में सहायता कर सकता है, भारत को अपनी विनिर्माण संबंधी आकांक्षाओं को साकार करने में सक्षम बना सकता है, दीर्घकालिक निवेश आकर्षित कर सकता है और विकास को प्रोत्साहित कर सकता है। ऐसी

वृद्धि टिकाऊ और 'रोजगार-सुग्राही' होगी, अर्थात् ऐसी वृद्धि जो श्रमिकों के दीर्घकालिक कल्याण को भी बढ़ाती है।

5.58 हालांकि बड़ी कंपनियाँ श्रम-प्रधान वृद्धि के स्थान पर पूंजी-प्रधान वृद्धि को प्राथमिकता देती हैं, किन्तु सूक्ष्म और मध्यम उद्यमों में दोनों के बीच बेहतर संतुलन होने की संभावना है, जिससे रोजगार सृजन को बढ़ावा मिलेगा। यह इस बात को सुनिश्चित करने के लिए एक अनिवार्य कारण है कि राज्य उनके विकास में बाधा न बने। राज्यों के पास विनियामक सुधार करने का अवसर है जो सरकारों तथा सूक्ष्म और मध्यम उद्यमों के बीच वार्ता की प्रकृति को मौलिक बदलाव करता है। राज्य उद्यमों की आर्थिक क्षमता के प्रति संवेदनशील और अवसर लागत को कम करने वाले विनियमनों को अपनाकर सुविधाजनक और सहयोगात्मक संबंध को बढ़ावा दे सकते हैं।

5.59 पूरे विश्व में राष्ट्रों ने गैर विनियमन पर निरंतर ध्यान दिये जाने के लिए कार्यक्रम शुरू किए हैं। उदाहरण के लिए, संयुक्त राज्य अमेरिका ने प्रबंधन और बजट कार्यालय बनाया है। यह कार्यालय लागत-प्रभावशीलता के आधार पर संघीय सरकार में प्रस्तावित सभी विधायनों की जांच करता है। अमेरिका में भावी सरकार ने डिपार्टमेंट ऑफ गवर्मेंट इंफिशिएंसी स्थापित करके गैर विनियमन को बहुत महत्व दिया है। द इकोनॉमिस्ट में एक ऑप-एड में अर्जेंटीना के राष्ट्रपति ने आर्थिक विवेकशीलता और कम विनियामक बोझ की पैरवी की है[50]। इसी तरह, यूनाइटेड किंगडम की संसद ने बेटर रेगुलेशन फ्रेमवर्क को अपनाया है। इस फ्रेमवर्क के हिस्से के रूप में, संसद 'वन-इन, टू-आउट' सिद्धांत का पालन करते हुए सभी नए विधायन बनाती है, जिसमें व्यवसायों पर नए विनियामक बोझ के प्रत्येक पाउंड को विनियमन के अन्य क्षेत्रों से मौजूदा बोझ के दो पाउंड की पहचान करके और उसे हटाकर ऑफसेट करने की आवश्यकता होती है[51]। न्यूजीलैंड ने विधायनों की जांच करने और अनुपालन अनुभव को बेहतर बनाने के लिए निरसन और संशोधन का प्रस्ताव करने हेतु मिनिस्ट्री ऑफ रेगुलेशन की स्थापना की है। भारतीय राज्यों को इन वैश्विक अनुभवों से सीख लेनी चाहिए और अपने परिपेक्ष्यों के लिए प्रासंगिक महत्वपूर्ण उदाहरणों को अपनाना चाहिए।

5.60 निर्यात, पर्यावरण, ऊर्जा और उत्सर्जन की दृष्टि से चुनौतीपूर्ण विश्व में विकास के अवसर खोजने की आवश्यकता का तात्पर्य यह है कि हमें गैर विनियमन पर अधिक तत्परता के साथ कार्य करने की आवश्यकता है। विकास के घरेलू नियंत्रकों पर ध्यान देना कोई विकल्प नहीं बल्कि मजबूरी है। गैर विनियमन के बिना, अन्य नीतिगत पहलें अपने वांछित लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर पाएंगी। विनियमन और स्वतंत्रता का सही संतुलन भारत के लघु और मध्यम उद्यमों की रचनात्मक और उत्पादक क्षमताओं में वृद्धि कर सकता है, जिससे नवाचार, अधिक प्रतिस्पर्धा और समग्र समृद्धि हो सकती है। छोटे व्यवसायों को सशक्त बनाकर, आर्थिक स्वतंत्रता को बढ़ाकर और समान अवसर सुनिश्चित करके, सरकारें एक ऐसा वातावरण बनाने में सहायक हो सकती हैं जहां विकास और नवाचार न केवल संभव है बल्कि अपरिहार्य भी है। भारत की विकास आकांक्षाओं को पूरा करके ये सभी कार्य किए जाने अनिवार्य हैं।

50 XX माइली, जेवियर (20 नवम्बर, 2024)। 'अर्जेंटीना: द मेकिंग ऑफ एन इकोनोमिक मिरेकल?' https%@@www-economist-com@ the&world&ahead@2024@11@20@argentina&the&making&of&an&economic&miracle

51 व्यापार नवाचार और कौशल विभाग (2014). 'नए विनियमन पर नौवां वक्तव्य'

5.61 इस अध्याय में विनियमन के लिए सुझाए गए क्षेत्र केवल उदाहरणात्मक हैं। लेकिन इन्हें मूर्त रूप प्रदान किए जाने के बाद इनके कई लाभ और संभावित अनभिप्रेत लाभकारी परिणाम होंगे। विनियमन को समाप्त करने की दिशा में राज्यों द्वारा किए गए प्रयासों से उद्योगों में प्रोत्साहन मिलेगा, शासन में विश्वास बढ़ेगा, और यहां तक की अनुपालन में भी सुधार होगा क्योंकि शासन और शासित के बीच संबंध साझेदारी में बदल जाते हैं। दूसरा, एक बार जब कुछ विनियमों को निरस्त या सरल कर दिया जाता है, तो शेष विनियम उत्तरोत्तर आसान हो जाते हैं। यह किसी कार्य का क्रमवार करने जैसा है। एक बार एक कार्य के पूर्ण होने के बाद दूसरे का मार्ग प्रशस्त हो जाता है और उस कार्य को करना सरल हो जाता है। तीसरा, यह छोटे कार्यों के व्यापक प्रभाव (बटरफ्लाई इफेक्ट) की शुरुआत हो सकती है, जिसका उल्लेख इस अध्याय में पहले अलग संदर्भ में किया गया था। बटरफ्लाई इफेक्ट का तात्पर्य यह है कि छोटे कार्यों के बड़े परिणाम हो सकते हैं। विनियमन के छोटे-छोटे कार्य उद्यमिता, निवेश, नवाचार और विकास के बड़े अवसरों का सृजन कर सकते हैं।

******